अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

घोषणा पत्र २०२४



जनता की गर्जन

बंगाल विरोधियों का विसर्जन

तृणमूल करेगा अधिकारों का अर्जन



अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

घोषणा पत्र २०२४

निवेदन

2011 से पहले बंगाल पतन और बदहाली की स्थिति में था। आपके प्रबल समर्थन से, मैंने बंगाल को प्रगति के पथ पर ले जाने की कसम खाई है। मैंने इस कर्तव्य को पूरा करने और राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ताकि वे समृद्ध जीवन जी सके।

आज, बंगाल की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसकी जबरदस्त योजनाओं ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पिछले एक दशक में हमने जो विकासात्मक प्रगति की है, उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई है। बंगाल विरोधी ताकतों द्वारा दबाव, रुकावट और जानबूझकर की गई वित्तीय नाकेबंदी के बावजूद हमारा राज्य फल-फूल रहा है। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि बंगाल के प्रत्येक निवासी को उनका उचित अधिकार मिले।

जब हम बंगाल के विकास का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान 2014 से केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार अपने भ्रामक वादों, जानबूझकर राज्य को वंचित करने और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपमानजनक रवैये के माध्यम से बंगाल के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण साजिश रच रही है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बंगाल के लोगों से ₹6.65 लाख करोड़ का कर वसूला है, फिर भी *जमींदारों* ने हमारे राज्य के महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए ₹1.6 लाख करोड़ की विकासशील योजनाओं का फंड रोक दिया है। वे इतने निचले स्तर तक गिर गए हैं कि उन्होंने हमारे लोगों को *रोटी, कपड़ा, मकान* जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित कर दिया है।

इसके अलावा, जब भी हमारे राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाहों या वंचित नागरिकों ने इन बाहरी लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो उनका अपमान किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया या उन्हें हिरासत में लिया गया।

उनके अत्याचार की भयावहता पूरे देश में भी देखी जा सकती है। पिछले 10 वर्षों में, वे संविधान में निहित संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लगातार कमजोर कर रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, उन्होंने लगातार विपक्षी दलों की आवाज़ों को दबाने और उनकी जनविरोधी नीतियों पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर वर्ग - समाज का हर वर्ग उनके यातना से प्रताड़ित हैं. दूसरी ओर, उनके कुशासन के कारण प्रमुख सूचकांकों में भारत की वैश्विक स्थिति काफी खराब हो गई है।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब हम परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं, मैं दृढ़तापूर्वक यह सुनिश्चित करने का संकल्प लेती हूं कि सभी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता रहेगा, बंगाल और देश के हितों के खिलाफ काम करने वाली दुर्भावनापूर्ण ताकतों को रोका जाएगा।

इस उद्देश्य से एक वीजन-कम-मिशन के तहत बंगाल के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने और देश को परिवर्तनकारी बदलाव की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इस ब्लूप्रिंट को डिजाइन करते समय, हमने राज्य और राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ व्यापक परामर्श किया है। हमारे संकल्प वास्तव में *माँ, माटी, मानुष* की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

हमारे प्यारे राज्य और राष्ट्र को खतरे में डालने वाली विभाजनकारी और विनाशकारी ताकतों को हराने की शक्ति लोगों में निहित है। यदि हम (INDIA गठबंधन) केंद्र में सत्ता में चुने जाते हैं, तो हम आपके साथ किए गए हर *शपथ* को पूरा करेंगे। हम सभी धार्मिक समूहों (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आदि), अनुसूचित जातियों (राजबंशी, नमशूद्र, बागड़ी, आदि), अनुसूचित जनजातियों (संथाल, ओराओं, भूटिया, आदि), अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और भाषाई समुदायों को राष्ट्रभर में मेल-जोल के साथ शांतिपूर्वक सहनशील बनाए रखने का संकल्प निभाएंगे। मैं, ममता बनर्जी, आप सभी से हमारी भावना और दृढ़ता के प्रतीक, *जोड़ाफूल* के निशान पर अपना वोट डालने के लिए आग्रह करती हूं। आइए हम हमारी शांति और सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। हम सभी एक साथ मिलकर हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे, अपना हर संकल्प पूरा करेंगे। **तृणमूल कांग्रेस INDIA गठबंधन के साथ केंद्र में सरकार बनते ही इन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।**

जय हिंद! जय बांग्ला!

ममता बनर्जी



दीदी के शपथ

1 मज़दूरों को मिलेगी उचित आय, होगी उनकी सहाय

- सभी रोजगार कार्ड धारकों को 100 दिनों की गारंटी से काम मिलेगा और सभी श्रमिकों को ₹400 प्रति दिन की बढ़ी हुई न्यूनतम आई मिलेगी पूरे देश भर

2 देश भर, सबको मिलेगा घर

- सभी गरीब परिवारों को गरिमामय आवास की गारंटी होगी, जो सभी को सुरक्षित घर प्रदान करेगा

3 खतम होगी मेहँगे एलपीजी की लाचारी, हर रसोई घर में होगी खुशहाली

- सभी बीपीएल परिवारों को हर साल मुफ्त में 10 एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें साफ पकाने के ईंधन का पर्याप्त पहुंच मिल सके, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कार्यप्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा

4 दीदी का सुशासन, सबको मिलेगा मुफ्त राशन

- हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 5 किलोग्राम राशन (चावल, गेहूँ, अनाज) मुफ्त में दिया जाएगा
- राशन हर लाभार्थी के घर के दरवाजे तक बिना किसी खर्च के पहुँचाया जाएगा

5 हमारा विश्वास, होगा सबका विकास

- ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि हाशिए के समुदायों के युवाओं को उन्नति का मौका मिल सके
- 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह ₹1,000 (सालाना ₹12,000) किया जाएगा

6 किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, होगी उनकी खुशहाली असिमत

- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के किसानों को कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों के औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक होगा

7 दीदी का भरोसा, होगा पेट्रोल सस्ता

- पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें वहनीय स्तर पर सीमित की जाएंगी
- कीमतों में उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए एक 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' बनाया जाएगा

8 हमारी आवाज, युवाओं मिलेगी रोजगार

- 25 वर्ष की उम्र तक के सभी स्नातक और डिप्लोमा धारकों को उनके कौशल और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए अप्रेंटिसों को मासिक स्टाइपेंड दी जाएगी
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को ₹10 लाख तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे

9 स्वच्छ कानुन, स्वाधीन भारत

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को खत्म किया जाएगा और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स (एनआरसी) को बंद कर दिया जाएगा
- एकसमान नागरिक संहिता (यूसीसी) को भारत भर में लागू नहीं किया जाएगा

10 बंगाल बढ़ेगा, देश बढेगा

- 13 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को शिक्षा के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन ₹1,000 का और एक बार की देने वाले ₹25,000 का उद्योग, बंगाल की कन्याश्री योजना के अनुरुप, प्रदान किया जाएगा
- सभी महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता, बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना के अनुरूप, प्रदान की जाएगी
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़े हुए रकम के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा योजना से बदला जाएगा, जिसमें बंगाल की स्वास्थ्य साथी योजना के अनुरुप ₹10 लाख का कवर होगा



विषय सूची

शासन..... 10-17

अर्थव्यवस्था.....18-23

उद्योग..... 24-29

कृषि.....30-35

शिक्षा.....36-41

स्वास्थ्य सेवा 42-47

बुनियादी ढांचा..... 48-53

राष्ट्रीय सुरक्षा 54-57

महिला सशक्तिकरण 58-63

युवा..... 64-69

एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक कल्याण 70-75

सामाजिक सुरक्षा 76-79

संस्कृति 80-85

पर्यटन.....86-91

पर्यावरण एवं जैव विविधता.....92-97





निश्चित सुशासन, बिकसित बंगाल

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल को जवाबदेह और जन-केंद्रित सरकार मिलेगी जो परिवर्तनकारी शासन प्रदान करेगी
- सभी भारतीय राज्यों के संघीय अधिकारों को मजबूती से संरक्षित किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: भाजपा के सत्ता में आने के बाद से भारत का लोकतंत्र और भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता लगातार खतरे में है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने **बंगाल के राज्यपाल** को **बंगाल के हितों के खिलाफ** काम करने के लिए कठपुतली बना दिया है, इससे बंगाल के लोगों को सुशासन के लाभों से वंचित किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है

- *बंगाल विरोधी* भाजपा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में **334 केंद्रीय टीमों और एनएलएम** को तैनात कर बंगाल सरकार के दैनिक कामकाज में बाधा उत्पन्न किया है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल में कमजोर समुदायों के लोगों के **आधार कार्डों को एकतरफा निष्क्रिय कर दिया है**, जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो गए हैं

- **संघीय विरोधी** भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमारे देश में राज्य सरकारों के कामकाज में खुलेआम बाधा उत्पन्न की है, और गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकार द्वारा लिये गये **फैसलों को बाधित करने के लिए** बार-बार राज्यपालों का उपयोग किया है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में लोकतांत्रिक विरोधी दलों को व्यवस्थित रूप से कुचलने के लिए **ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया है**, 2014 के बाद से ईडी के 95% मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया है

- सत्ता की भूखी भाजपा ने **9 वर्षों में 9 लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई** सरकारों (अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (2एक्स), उत्तराखंड, पुडुचेरी) को गिराने के लिए हर गंदी राजनीतिक चाल चली है

- भाजपा के पाखंड की पराकाष्ठा इसकी **'वॉशिंग मशीन राजनीति'** में स्पष्ट है - वर्षों से, इसने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के लिए जोरदार आरोप लगाए हैं, बाद में उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया, और उनके शामिल होने पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए

- **दिल्ली और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारियां** इस बात को उजागर करती हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किस हद तक प्रतिद्वंद्वी राज्य सरकारों के कामकाज को बाधित करने और उनके लोगों के जनादेश का अपमान करने के लिए तैयार है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले एक वर्ष से मणिपुर जल रहा है और इस दौरान यहां **200 से अधिक हत्याएं, 70,000 परिवारों विस्थापन और हजारों घर तबाह हुए हैं**

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसदीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है. इसने बेरहमी से **146 सांसदों को निलंबित कर दिया**, लगभग **300 प्रश्नों को रिकॉर्ड से हटा दिया**, साथ ही महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश के माध्यम से या **बिना बहस के पारित कर दिया**, और सदन में एक उपाध्यक्ष नियुक्त करने से भी साफ इनकार कर दिया

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नागरिकों की डिजिटल स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है. आधार उल्लंघन (2023) के दौरान 81 करोड़ भारतीयों के **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा** को उजागर किया, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं आदि की जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया, और 2016 के बाद से दर्जनों बार **इंटरनेट शटडाउन** लागू किए हैं

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को **161/180** देशों में स्थान दिया गया है (जो कि पाकिस्तान से भी नीचे है), यह दर्शाता है कि भारत का मीडिया किस हद तक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: प्रत्यक्ष शासन पहल के माध्यम से जीवन में बदलाव

- बंगाल के **90%** नागरिकों को टीएमसी सरकार की विभिन्न सेवाओं और कल्याण कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है;
- *दुआरे सरकार* को राष्ट्रपति से प्लैटिनम पुरस्कार मिला, **6.6 लाख प्रशासनिक शिविरों** के माध्यम से **8.7 करोड़ सार्वजनिक सेवाएं** सीधे नागरिकों के घर के दरवाजे तक पहुंचाईं गयीं और उन्हें सुविधाएं प्रदान की गयीं
- *बांग्ला सहायता केंद्र* के माध्यम से **6.5 करोड़** नागरिकों को **12 करोड़** ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की गयी हैं, जो जमीनी स्तर के लोगों की सेवा करने के साधन के रूप में ई-गवर्नेंस का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है
- *सरासोरी मुख्यमंत्री* कार्यक्रम के तहत **3.43 लाख** नागरिकों के सुझाव और शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसके माध्यम से 60,000 सेवाएं प्रदान की हैं, सेवाओं के वितरण संबंधी समस्याओं का लगातार समाधान किया गया
- *पाड़ाय समाधान* के तहत, छोटे हस्तक्षेपों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय स्तर के **47,130** प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के मुद्दों और सेवा संबंधी समस्याओं को हल किया गया है

टीएमसी सरकार ने क्या करने का संकल्प लिया है: संवैधानिक विध्वंस से कुशल शासन की ओर ध्यान केंद्रित करना

बंगाल के लिए

- **बंगाल सुशासन के लाभों का आनंद लेता रहेगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि बंगाल अन्य सभी के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में आगे बढ़े।

  निर्वाचित सांसदों का हमारा दल एक प्रेरित, उच्च-अखंडता, जवाबदेह प्रशासन के रूप में कार्य करने के लिए मिलकर काम करेगा, जो साल में 365 दिन बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और उनकी सेवा करेगा. हम यह सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन मोड' में अथक प्रयास करेंगे कि विकास, न्याय और समृद्धि हर कोने और हर घर तक पहुंचे।

- **पश्चिम बंगाल को आधिकारिक रूप से 'बांग्ला' के रूप में पुनर्नाम दिया जायेगा।** हमारे राज्य की इच्छाओं और प्रशासनिक सुविधा के लाभ के संरेखण में, हम अपने राज्य का नाम 'पश्चिम बंगाल' से 'बंगला' में बदलेंगे।

  ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव पहले ही राज्य विधानसभा द्वारा मंजूर किया गया था, और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था, फिर उसकी तानाशाहीबाजी से अस्वीकृति के बाद, 2018 में। हम इस मुद्दे पर अपने प्रयासों को दोहराएंगे और भारत के माननीय राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के साथ सकारात्मक ढंग से जुड़ेंगे ताकि हमारे राज्य के नाम को बदलने का एक स्पष्ट प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए और इसके बाद क्रियान्वित किया जाए।

- **ई-गवर्नेंस को सरकारी विभागों में और अधिक गहराई से एकीकृत किया जाएगा।** टीएमसी हमारे राज्य के शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।

  डैशबोर्ड की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से, रीयल-टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स और ऑनलाइन फीडबैक मैकानिज्म के साथ, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यान्वयन में प्रगति से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध हो, जिससे शासन में अधिक नागरिक भागीदारी संभव हो सके।

- **ब्लॉक स्तर पर प्रमुख स्थानीय प्रशासनिक और ढांचागत आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।** टीएमसी स्थानीय स्तर की नागरिक चिंताओं के प्रति शासन की प्रतिक्रिया के स्तर को बढ़ाएगी।

  स्थानीय रुप से प्रासंगिक बुनियादी ढांचागत जरूरतों को निर्धारित करने और प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए एक जन-संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें एमपी से लेकर पंचायत स्तर तक सभी स्तरों से निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी होगी। राज्य में हर साल एक के बाद एक शुरू किये जा रहे नये कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास किये जायेंगे।

  नागरिकों के साथ सीधे परामर्श के माध्यम से, इन मुद्दों को एकत्रित किया जाएगा और इसके लिए बजट को तेजी से मंजूरी देते हुए निश्चित समयसीमा के अंदर समाधान किया जाएगा।

- **दुआरे सरकार एवं पाड़ाय समाधान का आयोजन नियमित रुप से होता रहेगा।** टीएमसी बंगाल के घरों के दरवाजे तक सुशासन की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करेगी।

  दुआरे सरकार और पाड़ाय समाधान की अभूतपूर्व सफलता के कारण, ये पहल नियमित रुप से आयोजित की जाएंगी. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ और सेवाएं इसके लाभार्थियों के घर तक पहुँचें।

देश के लिए

- **सभी राज्यों के संघीय अधिकारों को मजबूती से संरक्षित किया जाएगा।** टीएमसी लाएगी एक संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 155 में। इससे सुनिश्चित होगा कि गवर्नरों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं के सलाह में की जाती है।

  हम पूरी तरह से जीएसटी प्रणाली को न्यायसंगत राजस्व वितरण के एक उपकरण में पुनर्गठित करेंगे। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुधारेंगे ताकि हर राज्य की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। हम संघ की वित्तीय जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन पर विभिन्न अनुदानों की असममिति को और भी सुधारेंगे। हम 'एक देश एक चुनाव' प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा, सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों की विकासात्मक और योजना संबंधी आवश्यकताएं संघ सरकार की तुलना में हैं, हम पूरे राज्यों के विकासात्मक और योजना संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए पूरे राज्यों के लिए एक केंद्र-राज्य बहुमत वार्ता के लिए एक मंच स्थापित करेंगे, जो योजना आयोग की तरह होगा।
- **भारत की दशकीय जनसंख्या जनगणना का अगला दौर आयोजित किया जाएगा।** टीएमसी देश की जनसंख्या जनगणना का संचालन सुनिश्चित करेगी, जो 2011 के बाद से नहीं हुई है।

  हम भारत की जनसांख्यिकीय जनगणना के अगले दौर की योजना बनाएंगे और उसका संचालन शीघ्रता से करेंगे। दशकीय अभ्यास के सभी भविष्य की गणनाओं में बेहतर डेटा गुणवत्ता को सक्षम करने के लिए पिछली जनगणनाओं

(वर्षों के आधार पर, मुद्रास्फीति, घरेलू खपत इत्यादि) में उपयोग की जाने वाली पद्धतियों के वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

इसके अलावा, हम पिछले वर्षों की 'नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी' की समीक्षा करेंगे और इस पर रिपोर्ट जारी करेंगे ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, और शिक्षा सहित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए अंतरिम जानकारी का उपयोग किया जा सके।

- **सरकारों को गिराने की प्रथा को दृढ़तापूर्वक अक्षम कर दिया जाएगा।** टीएमसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को अवैध रूप से गिराने के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी।

  हम दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे।

- **भारत की न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता बहाल की जायेगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की न्यायपालिका राजनीतिक दबावों या प्रलोभनों से मुक्त रहे।

  सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार, अनुच्छेद 99 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, हम एक तटस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की निगरानी करेगा, इसके मूल्यांकन मानदंड और विचार-विमर्श सार्वजनिक किए जाएंगे।

  हितों के टकराव को कम करने के लिए, हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी नियुक्तियां स्वीकार करने से पहले अनिवार्य रूप से 3 साल का 'कूलिंग-ऑफ अवधि' भी स्थापित करेंगे।

- **सरकारी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप ख़त्म किया जायेगा।** टीएमसी सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) जैसे निकायों की स्वायत्तता बहाल करेगी और इसके लिए इन संस्थाओं के परिचालन निर्णयों में केंद्र की भूमिका को विनियमित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जायेगा।

  इन संस्थानों के प्रशासन को स्वतंत्र पैनल द्वारा संचालित पारदर्शी चयन प्रक्रिया और संस्थागत अखंडता को प्राथमिकता देने वाले सख्त पात्रता प्रोटोकॉल के आधार पर की गयी नई नियुक्तियों से भी बदला जाएगा।

- **संसद में नया डिजिटल लिबर्टीज बिल पेश किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों, अनुचित निगरानी और उनके डिजिटल अधिकारों से वंचित होने से बचाया जाए।

  हम नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद में एक नया डिजिटल स्वतंत्रता विधेयक पेश करेंगे:
  - सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण और उचित उपयोग के लिए सुरक्षा प्रावधानों को मजबूत करने के लिए नए नियम बनाये जायेंगे।
  - प्राइवेट सिटिजन, मीडिया या राजनेताओं की जासूसी करने के लिए निगरानी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नए नियम बनाये जायेंगे।
  - इंटरनेट शटडाउन को एकतरफा लागू करने से रोकने के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का एक अच्छी तरह से परिभाषित सेट तैयार किया जायेगा।

- **हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में शांति बहाल की जाएगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और वहां शांति व्यवस्था बहाल की जाए।

  हम मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपाय करेंगे, जैसे:

  - प्रभावित समूहों के साथ बातचीत शुरु करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों को शामिल करते हुए एक पीस एंड रिकांसिलिएशन कमीशन की स्थापना की जायेगी।
  - निर्दिष्ट फास्ट-ट्रैक अदालतों में त्वरित सुनवाई के लिए जघन्य अपराधों के अपराधियों की जांच और पहचान करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जायेगा।
  - हिंसा प्रभावित अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की रणनीतिक वृद्धि, साथ ही अवैध रूप से हथियार रखने वाले व्यक्तियों से हथियार बरामद करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
  - जिन व्यक्तियों ने अपने घर खो दिए हैं उनके लिए नए घर बनाने और उन्हें मुआवजा देने के साथ-साथ उनका पुनर्वास करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना का विकास किया जायेगा।

- **केंद्र और राज्यों की एक राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआईसी) का गठन किया जाएगा।** टीएमसी भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने और वैमनस्य से उत्पन्न खतरों का प्रबंधन करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कदम उठाएगी।

  पुंछी आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार, हम सांप्रदायिक गड़बड़ी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना करेंगे:

  - परिषद कम से कम एक वार्षिक बैठक आयोजित की जायेगी।
  - देश में कहीं भी कोई गंभीर सांप्रदायिक घटना होने पर परिषद द्वारा नामित 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 5 दिनों के अंदर प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगा।

- **पूरे भारत में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी शुरु की जाएगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं को सभी नागरिकों तक आसानी से उनके घर पर पहुंचाया जाये।

  बंगाल मॉडल से सीखते हुए, जहां पुरस्कार विजेता दुआरे सरकार कार्यक्रम ने 2020 से 6.6 लाख प्रशासनिक शिविरों के माध्यम से 8.7 करोड़ सार्वजनिक सेवाएं सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाई हैं, हम इस पहल को पूरे देश में लागू करने के लिए तैयारी करेंगे।

  वर्ष में दो या तीन बार आवधिक अंतराल पर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर स्थापित शिविरों के माध्यम से, देश के नागरिक आवश्यक सरकारी सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र जारी करना या अद्यतन करना, कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करना या पात्रता एकत्र करना आदि का लाभ न्यूनतम प्रतीक्षा समय में व त्वरित गति से यहां से प्राप्त कर सकेंगे।

- **पूरे भारत में डिजिटल सहायता केंद्र स्थापित किये जायेंगे।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं भी सभी नागरिकों की आसान पहुंच के भीतर हों।

  एक बार फिर बंगाल मॉडल से सीखते हुए, जहां बांग्ला सहायता केंद्रों (बीएसके) ने 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों को 12 करोड़ से अधिक ऑनलाइन सेवाएं मुफ्त में सफलतापूर्वक प्रदान की हैं, हम पूरे देश में ई-गवर्नेंस तक हर आम नागरिक की पहुंच आसान बनाने के लिए इसी तरह के ई-सेवा केंद्र स्थापित करेंगे।

  इनके माध्यम से सभी नागरिकों को सरकार से उनकी सेवाओं का लाभ निःशुल्क, तेज और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- **राज्य-वित्त पोषित चुनावों की प्रथा शुरु की जाए।** टीएमसी भारत में राज्य-वित्त पोषित चुनावों की शुरुआत करके भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाएगी।

हम उन देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएंगे जहां सरकार द्वारा वित्त पोषित चुनाव सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं. यह पहल सभी राजनीतिक संस्थाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी, काले धन और कॉर्पोरेट फंडिंग के प्रभाव को कम करेगी, जिससे चुनाव और अधिक पारदर्शी व न्यायसंगत तरीके से आयोजित होंगे।







आर्थिक बिकास, सामाजिक समृद्धि

मुख्य लक्ष्य

- आगामी 5 वर्षों तक बंगाल की अर्थव्यवस्था एक मजबूत डबल-डिजिट वृद्धि दर का बनाए रखेगी
- सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 10 एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें स्वच्छ पाकन ईंधन की पर्याप्त पहुंच हो, इससे पर्यावरण के मित्रवत प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके
- जीएसटी प्रणाली का एक समग्र सुधार किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: भारत के एक समय की समृद्ध अर्थव्यवस्था को भाजपा ने गर्त में डाल दिया है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य से पिछले 5 वर्षों में करों के रूप में **₹4.6 लाख करोड़** से अधिक एकत्र करने के बावजूद, बेशर्मी से **₹6.65 लाख करोड़** की **धनराशि रोककर** बंगाल के लोगों को उनके उचित अधिकार से वंचित कर दिया है
- आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की जेब में छेद कर दिया है, देश भर में घरेलू बचत 2023 में **पांच दशक के निचले स्तर** पर आ गई है
- मोदी और भाजपा ने 'अच्छे दिन' का वादा करके वोट हासिल किए, लेकिन उनके **'विष काल' के दौरान,** आटा (↑31%), अरहर (तुर) दाल (↑40%), और दूध (↑50%) जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की **कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि हुई**, जिसने मध्यम और गरीब वर्ग को तबाह कर दिया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत भारत ने **ईंधन और एलपीजी की अब तक की सबसे ऊंची कीमतें** देखी हैं - यात्रा करना और खाना बनाना आम आदमी के गले की फांस बन गया है
- वैश्विक स्तर पर, भारतीय **रुपया अपने घुटनों पर** है, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की **जीएसटी प्रणाली** एक **निरंतर आपदा** बनी हुई है - इसने राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कमजोर कर दिया है, उनके बकाये के भुगतान में देरी की है, और इससे राजस्व वितरण में भेदभाव बद से बदतर हो गया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से **₹100 लाख करोड़ का कर्ज़ इकट्ठा कर लिया है - आज़ादी के बाद से पिछली 14 सरकारों की कुल राशि से दो गुना अधिक है -** आज देश का **प्रति व्यक्ति ₹1.2 लाख रुपये** के कर्ज का बोझ है.
- **ऐसी लापरवाही** केंद्र ने स्वयं अपनी एफआरबीएम उधार सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्यों की बुनियादी सीमा तक उधार लेने की क्षमता पर पाखंडी रूप से **प्रतिबंध लगा दिया है**

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: बंगाल की एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था को टीएमसी सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया गया और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया

- बंगाल **भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बनने के लिए तैयार है - हमारी जीडीपी 2011-12 में ₹5.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹18.8 लाख करोड़ हो गई है (भारत की वृद्धि से 2 गुना अधिक)
- हमारे नागरिक लगातार समृद्ध हो रहे हैं - प्रति व्यक्ति औसत आय 2011-12 में ₹51,543 से लगभग **तीन गुना बढ़ कर** 2022-23 में ₹1,41,373 रुपये हो गयी है
- पिछले दशक में, बंगाल ने अपना **निर्यात दोगुना से अधिक** कर लिया है, जो 2010-2011 में ₹55,589 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹1.1 लाख करोड़ हो गया है
- पिछले 13 वर्षों में बंगाल का बजट **चार गुना** से भी अधिक बढ़ गया है, यह 2011-12 में ₹84,804 करोड़ की तुलना में 2024-25 में बढ़ कर ₹3.66 लाख करोड़ (केंद्रीय बजट में वृद्धि से 50% अधिक) हो गया है

- बंगाल का अपना कर राजस्व संग्रह **चार गुना** बढ़ गया है, यह 2010-11 में ₹21,128 करोड़ से 2022-23 में बढ़कर ₹83,608 करोड़ रुपये होकर नयी ऊंचाइयों को छू रहा है
- **बंगाल का राजस्व घाटा** (जीएसडीपी के % के रूप में) 2010-11 में 3.75% से **घटकर** 2022-23 में 1.78% हो गया है
- **बंगाल का पूंजीगत व्यय आठ गुना से अधिक बढ़ गया है**, 2010-11 के मात्र ₹2,633 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹22,753 करोड़ हो गया है

टीएमसी ने क्या करने का संकल्प लिया है: आम आदमी को महंगाई की मार से बचाना, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता बहाल करना

बंगाल के लिए

- **अगले 5 वर्षों तक बंगाल की अर्थव्यवस्था के मजबूत दोहरे अंक की विकास दर बरकरार रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।** टीएमसी सुनिश्चित करेगी कि बंगाल का विकास का इंजन तेज गति से चलता रहे.

  बंगाल की जीएसडीपी 2023-24 में ₹17.2 लाख करोड़ थी, जो 10.6% की दर से बढ़ रही है, और जो आगे 10.5% की दर से बढ़ कर 2024-25 में ₹18.8 लाख करोड़ हो जाएगी, भारत में 'शीर्ष 5' अर्थव्यवस्था बनने की हमारी 2021 की प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल इस दोहरे अंक की विकास दर को बनाए रखे।

  प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और बुनियादी ढांचे को सक्षम करके, जिससे राज्य में उत्पादकता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा, इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ती रहेगी और फलती-फूलती रहेगी।

- **अगले दशक में बंगाल का निर्यात दोगुना किया जाएगा।** टीएमसी बंगाल को 'भारत का वैश्विक व्यापार केंद्र' बनाने का प्रयास करेगी।

  पिछले दशक में, बंगाल ने अपने निर्यात को दोगुना से अधिक कर दिया है, जो 2010-2011 में ₹55,589 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹1.1 लाख करोड़ हो गया है. पश्चिम बंगाल निर्यात संवर्धन नीति और पश्चिम बंगाल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकास नीति के संचालन के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम 2030 तक भारत के कुल वार्षिक निर्यात में अपने राज्य की हिस्सेदारी 2.9% से दोगुना कर 5.8% तक पहुंचा दें।

- **बंगाल में गरीबी का स्तर 1% से भी कम किया जाएगा।** टीएमसी हमारे राज्य में गरीबी खत्म करने के लिए अथक प्रयास करेगी।

  हम कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करके और अगले 10 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके बीपीएल लोगों के अनुपात को 8.6% से घटाकर 1% से भी कम करने का सफल प्रयास करेंगे:

  - 'सैचुरेशन मोड' में कल्याण, जिसमें सरकारी सहायता के लिए पात्र हर व्यक्ति *दुआरे सरकार* जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव या बहिष्कार के इसका उपयोग कर सकता है
  - बुनियादी सुविधाएं: सभी लोगों को घर, बिजली, एलपीजी, नल का पानी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

- **बंगाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार बेहतर बनाया जाएगा।** बंगाल को व्यापार और उद्योग के लिए एक शीर्ष गंतव्य बनाने की हमारी चल रही प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम अगले 5 वर्षों में अपने राज्य को भारत में 'शीर्ष 5' व्यापार गंतव्य बनाने के उद्देश्य से व्यापक ईओडीबी सुधार करना जारी रखेंगे।

- **बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब 2025 तक चालू हो जाएगा।** टीएमसी बंगाल को तकनीकी उद्योग में कुशल नौकरियों के लिए शीर्ष गंतव्य बनाने के अपने प्रयासों में तेजी लाएगी।

  सभी वैधानिक स्वीकृतियों पर तेजी से नज़र रखते हुए, हम कोलकाता में ₹1,00,000 करोड़ के निवेश से स्थापित कियो जा रहे टेक हब को 2025 के अंत तक पूरी तरह से चालू कर देंगे. इसके परिणामस्वरूप 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ-साथ निकटवर्ती व्यवसायों जैसे कि रियल एस्टेट और आतिथ्य सेक्टर में 50,000 अन्य नौकरियों का सृजन होगा।

देश के लिए

- **पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें किफायती स्तर पर सीमित की जाएंगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के आम लोग ईंधन और रसोई गैस खरीदने में सक्षम हों और कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से सुरक्षित रहें।

  - पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की दरों पर मूल्य सीमा लागू की जाएगी ।

  - वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में बदलाव के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं की लागत में संभावित बढ़ोतरी को संतुलित करने के लिए एक प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड बनाया जाएगा ।

  - पेट्रोल और डीजल की कमी को कम करने के लिए और 30-दिवसीय बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक राष्ट्रीय पेट्रोलियम रिजर्व भी बनाया जाएगा ।

- **प्रत्येक बीपीएल परिवार को बिना किसी मूल्य के 10 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के हर घर को किफायती कीमत पर खाना पकाने का ईंधन मिले।

  हम भारतीय परिवारों पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए हर साल सभी बीपीएल परिवारों को बिना किसी मूल्य के 10 एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करेंगे।

- **जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाएगा: वर्तमान जीएसटी व्यवस्था,** जिसने हमारे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को खत्म कर दिया है और भारी नुकसान का कारण बना है, इसका राजस्व वितरण के लिए और अधिक न्यायसंगत साधन के रूप में सुधार किया जाएगा।

  - राजस्व जारी करने में मौजूदा देरी को खत्म करने के लिए, जीएसटी संग्रह का प्रबंधन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अपने उचित शेयर एकत्र करने और अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।

  - उपरोक्त के लिए उचित मानदंड निर्धारित करने के लिए, जीएसटी परिषद को अधिक सर्वसम्मति-आधारित निकाय में परिवर्तित किया जाएगा और राज्य और केंद्र के बीच आनुपातिक वितरण निर्धारित करने का निर्देश दिया जाएगा ।

  - आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, गेहूं, खाना पकाने के तेल आदि पर जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी।

  - महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों (उर्वरकों, कीटनाशकों) पर जीएसटी कम किया जाएगा।

- **राज्यों को अपने वित्तीय उधार क्षमता निर्धारित करने का अधिकार बहाल किया जाएगा।** टीएमसी राज्यों की उधार लेने की क्षमता पर असममित सीमा को समाप्त करके उधार लेने पर केंद्र के दोहरे मानकों को समाप्त कर देगी।

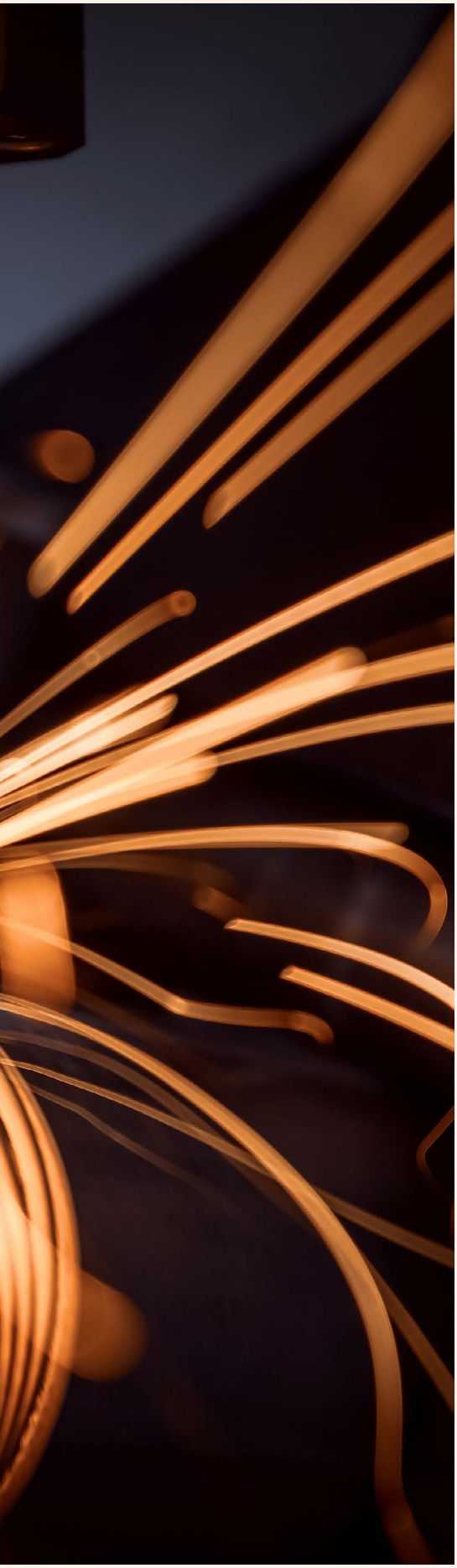
  हम राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और विशेष प्रयोजन वाहनों के ऑफ-बजट उधार को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के दायरे में रखने के केंद्र के फैसले को रद्द कर देंगे।
  हम केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहकारी ऋण प्रबंधन हासिल करने के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-सरकारी एफआरबीएम परिषद की भी स्थापना करेंगे।

- **मौजूदा कराधान नीतियों और मानदंडों की व्यापक समीक्षा की जाएगी**। टीएमसी भारत में मौजूदा कराधान प्रणाली पर फिर से विचार करेगी ताकि इससे लोगों पर से कर का बोझ कम किया जा सके।

  हम आयकर दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और इसे अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए टैक्स रिफॉर्म पेश करेंगे। कराधान को मुद्रास्फीति के मौजूदा स्तरों के अनुकूल बनाया जाएगा और निजी बचत व निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हम उपकरों की मौजूदा सीमा की भी समीक्षा करेंगे, जो राज्यों को कर राजस्व में उनका उचित हिस्सा देने से वंचित करती है







कौशल जनशक्तिका विकास, समग्र उन्नति का आधार

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के ग्रामीण कामगारों को *Karmasree* के माध्यम से नियमित रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा
- *MGNREGA* कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि 100 दिनों की नियुक्ती प्रदान की जाए, जिसका राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर दिन ₹400 हो

केंद्र सरकार ने क्या किया: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिक वर्ग के जीवन को तबाह कर दिया है

- भाजपा के अत्याचार के तहत, अमीर और अमीर हो गए हैं, जबकि गरीबों को नुकसान उठाना पड़ा है - भारत की धन असमानता **छह दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास 40.1% संपत्ति है** - जो ब्रिटिश राज के समय से भी अधिक असमान है

- पीएम मोदी का औद्योगिकीकरण का *'अमीरों का विकास, गरीबों का विनाश'* मॉडल **क्रोनी पूंजीवाद** का एक नग्न प्रदर्शन है, जो पूरे श्रमिक वर्ग की कीमत पर देश के मात्र **1% लोगों को प्राथमिकता देता है** - 2014 के बाद से **₹14.6 लाख करोड़** रुपये के ऋण माफी का आधा लाभ केवल बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को हुआ है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के **20 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों** के कुप्रबंधन की वजह से इसे कॉर्पोरेट हितों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, इन उद्यमों का निजीकरण हुआ है, जिससे दीर्घकालिक राजस्व स्रोतों और **1.5 लाख से अधिक नौकरियों** का नुकसान हुआ है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम एक बड़ी विफलता के रूप में सामने खड़ा है, देश में 2014 के बाद से महज 5.9% की औसत विनिर्माण विकास दर से पता चलता है कि भाजपा द्वारा किए गए ऊंचे वादे सिर्फ खोखली बयानबाजी है;

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने **'आत्मनिर्भर भारत'** योजना के तहत एमएसएमई को ₹3 लाख करोड़ के संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋण देने की गारंटी देने के बावजूद, उन्हें ऋण प्रदान करने में विफल रही है, जिसकी वजह से अनगिनत संघर्षरत **एमएसएमई यूनिट का कारोबार अधर में अटक गया है**

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी के कार्यकाल में, बंगाल का उद्योग

- बंगाल ने **1.3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार** देकर अपने एमएसएमई क्षेत्र को सुपरचार्ज किया है. 2011 से अब तक **57 लाख नए एमएसएमई** जोड़े गए हैं, इनके लिए 2011 से 2023 तक बैंक क्रेडिट के रूप में **₹6 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किये गये हैं

- बंगाल का **विनिर्माण 7.8%** की दर से बढ़ा है, जो 2022-23 में राष्ट्रीय विकास दर 5% से अधिक है

- बंगाल में कारखानों की संख्या 2010 में 8,232 से **17% बढ़कर** 2021 में 9,650 हो गई है

- **26 आईटी पार्क** के परिचालन से बंगाल का आईटी क्षेत्र पूर्ण रूप से बदल गया है

- चाय बागान श्रमिकों के लिए मजदूरी 3 गुना बढ़ा दी गई है, जो 2011 में **₹67 प्रति दिन से बढ़कर वर्तमान में ₹250 प्रति दिन हो गई है।** इसके अतिरिक्त, लगभग **23,000 चाय बागान मालिकों को होमस्टेड पट्टे दिए गए हैं**

- बंगाल का हथकरघा उद्योग 5.4 लाख (कुल का 17.3%) लोगों को रोजगार देने के साथ भारत में रोजगार देने में **दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर** है

टीएमसी ने क्या करने का संकल्प लिया है: एक समावेशी उद्योग क्षेत्र का निर्माण करना, जो स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करे और नौकरियों के साथ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए

बंगाल के लिए

- **बंगाल के ग्रामीण कार्यबल को रोजगार की गारंटी दी जाएगी।** टीएमसी केंद्र को मनरेगा फंड रोककर हमारे लोगों के काम करने के अधिकार को छीनने की अनुमति नहीं देगी।

  कर्मश्री योजना के माध्यम से, हम प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को कम से कम 50 दिन का काम प्रदान करेंगे.
  इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने पहले ही 50 लाख से अधिक श्रमिकों के लिए वेतन जारी कर दिया है, जिन्हें केंद्र के धन से इनकार करने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

- **बंगाल के लिए एक नई भविष्योन्मुखी विनिर्माण नीति बनाई जाएगी।** हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि बंगाल का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रहे।
  हम अपने उभरते उद्योगों (आईटी, कपड़ा, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और जलीय कृषि, आदि) और प्रमुख उद्योगों (रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, लौह और इस्पात, आदि) के लिए एक नई नीति विकसित करेंगे, जो निम्नलिखित पर केंद्रित होगी:

  - बंगाल के भीतर विनिर्माण और निर्माण की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण (प्लग-एंड-प्ले कारखाने और कार्यस्थल, पावर ग्रिड, इंटरनेट और टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, आदि)
  - उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से इन उद्योगों में कार्यबल के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली घरेलू प्रतिभा की एक पाइपलाइन विकसित करना

- **बंगाल में चाय और जूट उद्योग को और विकसित किया जाएगा।** टीएमसी हमारे राज्य के महत्वपूर्ण चाय और जूट उद्योगों की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करेगी।

  - बार-बार होने वाले श्रम व्यवधानों को खत्म करने के लिए, वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की समीक्षा करने और यूनियनों के साथ जुड़ने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा
  - उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आधुनिक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे (चाय कारखानों के लिए हार्वेस्टर और रोलिंग/सुखाने के उपकरण, जूट मिलों के लिए कार्डिंग, कताई और बुनाई के लिए मशीनरी)
  - स्थानीय और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण का एक मजबूत नया सेट पेश किया जाएगा

- **कार्यात्मक एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या को 1.5 करोड़ तक बढ़ाने के लिए हर साल अतिरिक्त 10 लाख एमएसएमई जोड़े जाएंगे।** टीएमसी उद्यमिता को बढ़ावा देकर बंगाल में नौकरियां पैदा करना जारी रखेगी।

  हम अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे और वित्त और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके, घरेलू और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों तक आसानी से पहुंच प्रदान करके, एमएसएमई और बड़े उद्योगों के बीच व्यापार संबंध बनाकर और स्थानीय लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक बुनियादी ढांचे का विकास करके हर साल 10 लाख अतिरिक्त एमएसएमई को जोड़ेंगे। अतिरिक्त एमएसएमई, पहले की तरह, मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और राज्य में अधिक नौकरियां पैदा करेंगे

- **बंगाल के प्रत्येक जिले में फसल-विशिष्ट फूड पार्क की स्थापना की जाएगी।** टीएमसी स्थानीय उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय करके हमारे कृषक बंधुओं का समर्थन करेगी.

  प्रत्येक जिले की विशिष्ट फसल आवश्यकताओं के अनुरूप, फूड पार्क किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट, उचित मूल्य और बेहतर खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे तक पहुंचने में मदद करेंगे।

  सभी पार्क मजबूत बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण

(वजन, छंटाई, उपज की ग्रेडिंग) की सुविधा के लिए संग्रह केंद्र और खेतों से सुदूर स्थानों तक फसल के हस्तांतरण और भंडारण के लिए अत्याधुनिक कोल्ड चेन इन्फ्रा शामिल होंगे।

- **बंगाल में कारीगर समुदायों को वर्किंग कैपिटल के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।** हम 2 लाख कारीगरों को सम्मानजनक आजीविका कमाने और राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में सहायता करेंगे।

  पेशेवर उपकरण खरीदने या वर्क शेड के निर्माण/मरम्मत के लिए ₹15,000 तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। समय के साथ और अधिक कारीगरों को इस योजना के तहत लाया जाएगा।

देश के लिए

- **एमएसएमई के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी, जिसमें ऋण और इनपुट तक व्यापक पहुंच पर जोर दिया जाएगा।** एमएसएमई हमारे राज्य के औद्योगिक विकास के इंजन की रीढ़ रहे हैं, और टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें पूरे देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित समर्थन मिले।

  - बंगाल मॉडल से सीखते हुए, जहां सहकारी बैंकिंग को एमएसएमई ऋण से जोड़ने से ऋण पहुंच में काफी वृद्धि हुई, नई राष्ट्रीय नीति पारंपरिक स्रोतों (बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आदि) के साथ-साथ गैर-पारंपरिक स्रोतों (व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी, आदि) के माध्यम से कम ब्याज पर एमएसएमई को ऋण की आपूर्ति करने के लिए एकल प्रणाली में शामिल किया जायेगा

  - इसके अलावा, ई-मंडियों, कृषि उपज बाजार समितियों, राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज आदि के लिंकेज के साथ सस्ती कीमतों पर सामग्री तक पहुंच के लिए कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच भी बनाया जाएगा

- **स्थानीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए जिलेवार, 'औद्योगिक उत्कृष्टता ब्लूप्रिंट' बनाए जाएंगे।** प्रत्येक जिले की पूर्ण आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए, टीएमसी स्थानीय रूप से जागरूक औद्योगिक कार्य योजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी जो 'एक जिला, एक उत्पाद' जैसी कमजोर नीतियों से परे होगी।

  यह केंद्र प्रमुख स्थानीय औद्योगिक अवसरों को निर्धारित करने, अंतराल और जरूरतों को समझने और स्थानीय औद्योगिक विकास को सक्षम करने, रोजगार पैदा करने के लिए अनुकूलित मिनी-क्लस्टर, स्मार्ट इन्फ्रा, लॉजिस्टिक्स और बाजार-पहुंच समाधान स्थापित करने के लिए ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ काम करेगा और इसके माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का लक्ष्य सुनिश्चित किया जायेगा।

- **मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना के 100 दिनों का कार्यदिवस प्रदान की जायेगा, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी ₹400 प्रतिदिन होगी।** टीएमसी मनरेगा कार्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी ताकि इस पर निर्भर सभी लोगों के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

  इस योजना से जुड़े लोगों के लिए बढ़ते समय के साथ आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रमिकों के वेतन को बढ़ाया जायेगा और देश भर में इसके सशक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दैनिक वेतन को बढ़ा कर ₹400 प्रतिदिन किया जायेगा।

- **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का विस्तार जाएगा।** टीएमसी और अधिक क्षेत्रों को पीएलआई में लाकर औद्योगिक रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देगी।

  हम कृषि-प्रसंस्करण, निर्माण और रियल एस्टेट और खुदरा और थोक व्यापार जैसे उच्च रोजगार सृजन क्षमता वाले और अधिक क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण-केंद्रित क्षेत्रों को पीएलआई योजना के तहत लाकर औद्योगिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे

- **अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश तैयार किया जाएगा।**

यह देखते हुए कि कैसे विमुद्रीकरण और कोविड के प्रभावों ने भारत के अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र की कामकाजी संभावनाओं को तबाह कर दिया है, जो हमारे देश में दैनिक-मजदूरी रोजगार का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता है, हम अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के मामलों के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना करेंगे।

हमारे दैनिक-मजदूरी को व्यावसायिक रूप से अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए वेतन, काम करने की स्थिति, श्रम कोड और सुरक्षा आदि में वृद्धि के लिए व्यवहार्य दीर्घकालिक नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारियों के साथ इस आयोग का गठन किया जायेगा।







फसलों में बढ़ोतरी, होगी किसानकी समृद्धि

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के किसानों के लिए कृषि मशीनरी को और अधिक पहुंचयोग्य बनाया जाएगा, और उनके लिए अधिक किसान उत्पाद संगठन (FPOs) बनाए जाएंगे
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के सभी किसानों के लिए न्यायिक रूप से MSP की गारंटी दी जाएगी

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र ने उन किसानों की गरिमा पर हमला किया है, जो हम सभी का पेट भरते हैं, जिससे भारत के किसान गंभीर संकट में हैं.

- **3 विवादास्पद कृषि कानूनों ने भारत के किसानों के प्रति भाजपा के असली इरादों को उजागर किया है**: उनके जीवन या आजीविका के लिए चौंकाने वाला तिरस्कार किया है. हमें खिलाने वालों की जरूरतों को पूरा करने की बजाय भाजपा ने अपने पसंदीदा क्रोनी कॉरपोरेट्स की जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा ध्यान दिया है

- केंद्र ने शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए खड़े किसानों को दबाने का हर संभव प्रयास किया, उन पर क्रूरतापूर्वक पुलिस की बर्बर कार्रवाई की गयी, **दर्जनों प्रदर्शनकारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया,** और उन्हें "खालिस्तानियों" का लेबल देकर उन पर अत्याचार किया गया

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हमारे किसानों की आजीविका के प्रति उपेक्षा इस बात से स्पष्ट है कि कैसे वह **एमएसपी** को कानूनी दर्जा देने में विफल रही है और **आवश्यक कृषि उत्पादों पर जीएसटी** लगाकर उनकी लागत बढ़ा दी है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों को **कर्ज के जाल में फंसाया** है. 2014 में कुल बकाया कृषि ऋण ₹9.64 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-2022 में ₹23.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गयी है

- पिछले 4 वर्षों में कृषि बजट का हिस्सा 4.4% से **घटकर** 2.5% हो गया है, जिससे बुनियादी ढांचे, सब्सिडी या सहायता कार्यक्रमों में न्यूनतम निवेश वाले किसानों को नुकसान हुआ है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को उनकी **आय दोगुनी** करने के खोखले वादों के साथ धोखा दिया, जिसमें आवश्यक 10% सालाना वृद्धि होने की बजाय यह केवल 3.5% बढ़ी है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अक्षमता स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है - इसने पीएम किसान के तहत **42 लाख फर्जी लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए** ₹3,000 करोड़ में से केवल 1/10वां हिस्सा ही वसूल किया है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: पिछले दशक में बंगाल के किसानों की किस्मत में अभूतपूर्व बदलाव आया है

- कृषि और संबद्ध सेवाओं का बजट **दस गुना बढ़ गया है,** जो 2010-11 में ₹2,274 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹22,620 करोड़ रुपये हो गया है

- *कृषक बंधु* योजना के तहत, **1 करोड़** से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को **₹10,000 प्रति वर्ष** की सहायता राशि प्रदान की जा रही है

- *बांग्ला शस्य बीमा* पहल के तहत, बंगाल के **70 लाख किसान** फसल बीमा कवरेज से लाभान्वित हो रहे हैं

- आज **पश्चिम बंगाल भारत में** जूट, धान और मेस्टा का अग्रणी उत्पादक है

- बंगाल भारत में मछली का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है, जिसने मछली के निर्यात को 59,774 मीट्रिक टन (2010-2011) से दोगुना करके 1,25,193 मीट्रिक टन (2022-23) कर दिया है

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: हमारे किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और उनके अधिकारों, हितों और आजीविका का प्रतिनिधित्व करें

बंगाल के लिए

- **किसानों के लिए कृषि मशीनरी तक पहुंच को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा।** टीएमसी किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में हर प्रकार से सहायता करेगी।

  हम अपने किसानों तक आसानी से मशीनरी उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए 2,000 कृषि मशीनरी हब (कस्टम हायरिंग सेंटर) स्थापित करेंगे।

- **किसानों की आय बढ़ाने के लिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशंस स्थापित किए जाएंगे।** टीएमसी हमारे किसानों के समर्थन के लिए एक प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करेगी।

  हम पूरे बंगाल में 1,200 अतिरिक्त फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशंस (एफपीओ) स्थापित करेंगे, ताकि हमारे किसान गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की थोक खरीद के माध्यम से अपनी आजीविका को बढ़ावा दे सकें और मंडियों में अपनी उपज की बिक्री का प्रबंधन करने के लिए स्वायत्तता बढ़ा सकें।

- **आलू उत्पादकों को बीमा प्रीमियम सहायता प्रदान की जाएगी।** टीएमसी बंगाल के 20 लाख आलू उत्पादकों की आजीविका उपार्जन के लिए हर प्रकार से समर्थन करेगी।

  हम बांग्ला शस्य बीमा योजना (फसल बीमा योजना) के तहत आलू की फसल के लिए प्रीमियम को कवर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के पास सभी मौसमों में सुरक्षित आय हो।

- **मछुआरों को ऑफ-सीजन में आजीविका उपार्जन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।** टीएमसी बंगाल के मछुआरों की आजीविका में सहायता प्रदान करेगी और ऑफ-सीजन के दौरान भी उनकी आमदनी सुनिश्चित करेगी।

  हम समुद्र साथी योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बंगाल के मछुआरों को ऑफ-सीज़न या समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान 2 महीने के लिए प्रति माह ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और फिर इस योजना को देश के बाकी हिस्सों में भी लागू जाएगा।

भारत के लिए

- **स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अपनाया जाएगा।** टीएमसी हमारे देश के किसानों के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करेगी।

  हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे और उसकी सिफारिशों के आधार पर, लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे, जिसके माध्यम से कानूनी रूप से ऐसी सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से अनिवार्य रूप से कम से कम 50% अधिक एमएसपी तय किया जा सके।

  प्रोक्योरमेंट के प्रबंधन के लिए एक प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड भी स्थापित किया जाएगा, जो समिति की सिफारिशों के अनुरूप होगा।

- **कृषि वस्तुओं पर मौजूदा निर्यात नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही पहले से बेहतर किसान-अनुकूल निर्यात नीति शुरु की जाएगी।** टीएमसी कृषि निर्यात के भविष्य को निर्धारित करने में किसानों की जरूरतों और हितों को दृढ़तापूर्वक प्राथमिकता देगी।

  दुनिया की केवल 2.4% भूमि और 4% जल संसाधन होने के बावजूद, भारतीय कृषि के निर्यात के माध्यम से दुनिया की 17.8% आबादी तक अनाज पहुंचाया जाता है।

  हमारे देश के किसानों की दुर्दशा में भारत के प्रचलित निर्यात नियंत्रणों की भूमिका को पहचानते हुए, हम कृषि वस्तुओं के लिए भारत की आयात-निर्यात नीति में व्यापक सुधार करेंगे, जिसके तहत नीति को और अधिक किसान-अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा:

  - निर्यात किये जाने वाले कृषि उत्पादों में तालिका में मूल्यवर्धित उत्पादों को शामिल किया जायेगा और इसके अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विविध रूप से तैयार किया जायेगा।
  - एक स्टैबल कमोटिडिटीज ट्रेडिंग पॉलिसी स्थापित की जाएगी - गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी, जिसके वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में भारत लीडरशीप का स्थान रखता था।
  - कोल्ड-चेन के लिए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के लिए निवेश बढ़ाया जाएगा, जिसमें फलों और सब्जियों के मूल्य को संरक्षित करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
  - कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश को मौजूदा कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से दोगुना कर कम से कम 1% किया जाएगा।

- **किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएंगे।** टीएमसी हमारे किसानों को अनावश्यक कानूनी मामलों से बचाएगी।

  अपने अधिकारों के लिए उनके साहसी संघर्ष की वैधता की मान्यता में, हम किसानों के विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों को तुरंत वापस ले लेंगे, समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करेंगे और नई भावी केंद्र सरकार के प्रति उनका विश्वास बहाल करेंगे।

- **मछुआरों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच को और आसान बनाया जायेगा.** टीएमसी मछुआरे समुदाय के बीच ऋण की उपलब्धता को और सुगम बनायेगी।

  मछुआरा समुदायों को वित्तपोषण के लिए संस्थागत स्रोतों के माध्यम से एकीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए, हम मछुआरों के लिए कोऑपरेटिव बैंक स्थापित करेंगे, जहां से वे बहुत ही सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

  हम मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करेंगे, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकें, साथ ही नावों और मछली पकड़ने के उपकरणों जैसी संपत्तियों के लिए ब्याज छूट और बीमा का लाभ उठा सकें ।







शिक्षा में प्रगति, समाज की उन्नति

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की जाएगी
- भारत के शिक्षा पर बजट का खर्च कुल बजट का 5% तक बढ़ाया जाएगा
- भारत भर में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: अनावश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से, केंद्र सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली को मिट्टी में मिला दिया है

- निचले स्तर तक गिरकर, भाजपा के जमींदारों ने **समग्र शिक्षा मिशन** के तहत बंगाल का **₹17,300 करोड़ रुपये का फंड रोककर** यहां के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अंतरिम कुलपतियों की मनमानी तरीके से नियुक्ति, पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज में जानबूझकर बाधा उत्पन्न और **विभिन्न आपत्तियों के माध्यम से छात्रों के भविष्य** को खतरे में डालने की कोशिश की है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक दयनीय पीआर एजेंट में बदल दिया है,** जिसका ध्यान अब 'सेल्फी पॉइंट' बनाने और विवादास्पद बिलों का विज्ञापन करने पर केंद्रित है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के लिए ₹9,000 करोड़ से अधिक की फंडिंग में भी कटौती कर दी गई है
- इतिहास का भगवाकरण करने के बेशर्म प्रयास में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में मनमाने ढंग से बदलाव करने और **भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं को प्रचारक स्वर में फिर से लिखने के लिए मजबूर कर रही है**
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ख़राब **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** राज्यों के संघवाद पर एक और हमला है एवं यह शिक्षा नीति प्रत्येक राज्य की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं, भाषाई आवश्यकताओं और परीक्षा प्रक्रियाओं को ध्यान में पूरी तरह रखने में विफल है
- 45 केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों में 18,956 स्वीकृत शिक्षण पदों में से, 2023 की शुरुआत तक लगभग **एक तिहाई (6,028) पद खाली पड़े थे**
- **₹23,000 करोड़ की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करके,** भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किफायती शिक्षा को भारत के लाखों ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की पहुंच से बाहर कर दिया है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: केजी से पीजी तक, टीएमसी ने शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच को बढ़ाया है

- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का बजट 2010-11 के ₹13,872 करोड़ से तीन गुना बढ़ा कर 2024-25 में ₹47,470 करोड़ कर दिया गया है;
- *कन्याश्री योजना* को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेस अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके माध्यम से **85 लाख से अधिक लड़कियों** को उच्च प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
- 2010 से यहां **30** नए विश्वविद्यालय, **52** कॉलेज, **298** आईटीआई, **202** पॉलिटेक्निक और **2,21,849** अतिरिक्त कक्षाएं बनाई गई हैं;
- संयुक्त राष्ट्र की अधीनस्थ डब्ल्यूएसआईएस से सम्मानित *सबूज साथी योजना* के तहत, राजय **1.25 करोड़** से अधिक छात्रों को **साइकिल प्रदान की गई है,** वहीं, **36 लाख छात्रों** को तरुणेर स्वप्नो योजना के तहत टैबलेट मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;
- अपनी योजनाओं की सफलता के कारण, बंगाल ने उच्च प्राथमिक स्तर पर **0% ड्रॉपआउट दर हासिल की है**

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: भारत की शिक्षा योजना के उन निर्णयों को फिर से केंद्रित करेंगे और जो लोगों के विकास के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं

बंगाल के लिए

- **बंगाल के उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी.** टीएमसी राज्य में उच्च शिक्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी:
  - हम जादवपुर विश्वविद्यालय को "उत्कृष्ट संस्थान" का दर्जा देने और इसकी शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को विश्व स्तरीय मानकों तक उन्नत करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
  - हम बंगाल में 143 उच्च शिक्षा संस्थानों की लंबित नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल (NAAC) मान्यता प्रक्रियाओं को फास्ट-ट्रैक तरीके से आगे बढ़ायेंगे।

- **विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के होगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए कुलपतियों की नियुक्ति बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के की जाए।

  हम 2018 यूजीसी विनियमों में संशोधन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश पेश करेंगे, ताकि राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित राज्य विधानसभाओं के परामर्श से की जाए।

- **राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।** टीएमसी हमारे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करेगी. हम राज्य के सभी 341 ब्लॉकों में स्कूलों के निर्माण या उन्नयन के माध्यम से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं के साथ तकनीकी रुप से सुसज्जित मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करेंगे।

- **छात्रों को शैक्षिक सहायता के रुप में टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराये जायेंगे।** टीएमसी बंगाल के छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता को किफायती ढंग से बढ़ावा देगी।

  बंगाल के छात्रों को डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक पहुंच बढ़ाने के लिए टैबलेट/स्मार्टफोन खरीदने के लिए हम प्रति छात्रों को तरुणेर स्वप्नो योजना के तहत ₹10,000 रुपये का अनुदान प्रदान करना जारी रखेंगे. इसके अलावा, इस योजना के योग्यता के मानदंडों को बारहवीं कक्षा की बजाय ग्यारहवीं कक्षा के लिए संशोधित किया जाएगा, ताकि छात्र इन उपकरणों का उपयोग 1 की बजाय 2 वर्षों तक कर सकें।

- **उत्तर बंगाल में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी-दार्जिलिंग की स्थापना की जाएगी।** रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र से पलायन को कम करने के लिए टीएमसी उत्तर बंगाल क्षेत्र को विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगी. हम पहाड़ी क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए दार्जिलिंग में बंगाल में एक और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे।

देश के लिए

- राज्यों की स्वायत्तता बहाल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया जाएगा। टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों की संस्थागत जरूरतों, सीखने की आवश्यकताओं और भाषाई मांगों की रक्षा के लिए प्रत्येक राज्य के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक संचालन समिति का गठन करके शिक्षा नीति को संशोधित किया जाए:
  - हम 5+3+3+2 संरचना को लागू नहीं करेंगे और इसके बजाय प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप

अपनी स्वयं की शैक्षिक संरचना का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

» हम देश भर में सामान्य प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर देंगे और राज्य शैक्षणिक संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के अधिकार बहाल करेंगे।

✢ **शिक्षा पर भारत का बजट व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा क्षेत्र को फिर से प्राथमिकता दी जाए।

हम कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के बेहद कम 0.3% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% करेंगे।

इस बढ़े हुए बजट को शिक्षा के मौलिक अधिकार में निहित प्रावधानों के माध्यम से इसको अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में पूरे देश में बारहवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को स्कूल ड्रेस, अध्ययन सामग्री, मध्याह्न भोजन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जाएगा. हम राज्य शिक्षा विभागों के परामर्श से राज्यों की जरूरतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग पर अपना खर्च जीएसडीपी के 6% तक बढ़ाया जा सके।

✢ **केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में सभी शिक्षण रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।** टीएमसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सभी कमी को दूर करने के लिए सभी शिक्षण रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता देगी।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे भारत में 45 केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों में 6,000 से अधिक रिक्तियां - जो सभी उपलब्ध पदों में से एक तिहाई हैं - इनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा के विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देते हुए एक वर्ष के भीतर भरी जाएं, जहां इनमें से लगभग आधे पद आज भी खाली हैं. ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्तियां सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

✢ **ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की संख्या तीन गुना की जाएगी।** टीएमसी शिक्षा के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवाओं के उत्थान में सहायता करेगी।

भारत के ओबीसी, एससी और एसटी के बीच शिक्षा पहुंच के अंतर को दूर करने और इस तरह इन समुदायों में मानव पूंजी के विकास को समृद्ध करने के लिए, हम उनके लिए उपलब्ध उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान की संख्या बढ़ाया जाएगा। डिग्री कार्यक्रमों, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के साथ-साथ डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले इन समुदायों के सभी छात्र ऐसी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

✢ **वंचित समूहों के लिए कक्षा I-VIII के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति फिर से शुरु की जाएगी।** ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के उत्थान के लिए एक व्यापक योजना के साथ, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति फिर से शुरु की जाएगी और इसकी संख्या तीन गुना की जाएगी।

» पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के तहत वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी एंड अदर्स (2021-22 से 2025-26) में कक्षा I-VIII के ओबीसी छात्रों को भी शामिल करने के लिए इसके दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा।

» इसी तरह, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत कक्षा I-X तक के छात्रों को कवर करने वाले नए दिशानिर्देश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

✢ **पेपर लीक के खतरे को रोकने के लिए एक नीति लाई जाएगी।** टीएमसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाले कदाचार को खत्म करेगी और हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखेगी।

हम निम्नलिखित प्रावधानों के साथ पब्लिक एक्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिंस) बिल 2024 में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे:

» प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की शुरु से अंत तक निगरानी के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग (केंद्र और राज्य स्तर) का गठन करेंगे।

» तीसरे पक्ष जैसे प्रश्न पत्रों की छपाई और परिवहन व्यवस्था को शामिल करने वाले विभिन्न चरणों का सख्त ऑडिट

करेंगे।

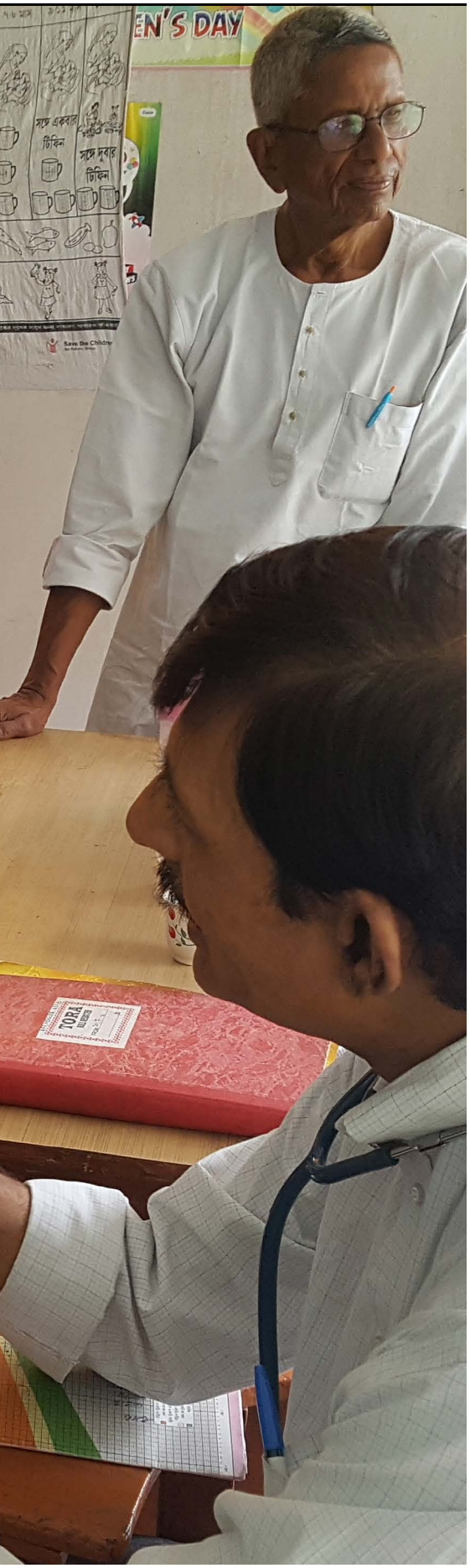
- » विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए फुल-प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेंगे।
- » परीक्षा आयोजित करने के लिए तृतीय-पक्ष एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय मानक और प्रोटोकॉल तैयार करेंगे।

✢ **स्कूली पाठ्यक्रम को प्रचार-प्रसार से मुक्त किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की स्कूली शिक्षा पूर्वाग्रह से मुक्त रहे।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए विषय विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन करेंगे, जिससे कि भारत भर में स्कूली पाठ्यपुस्तकों की सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए ऑडिट की जाए और भारतीय इतिहास व पौराणिक कथाओं के संदर्भ में प्रचार, सेंसर या तथ्यात्मक संशोधनवाद से मुक्त रहें. इसके माध्यम से, हम भारत के स्कूली पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव के तत्व को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे।




প্রাথমিক শুশ্রূষা
মশা নিয়ে কথা
শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ দিন



दीदी का वादा , सबको मिलेगी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा

मुख्य लक्ष्य

- आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर गली किनारों तक पहुँचाया जाएगा
- भारत के स्वास्थ्य बजट को कुल बजट का 6% तक बढ़ाया जाएगा
- *आयुष्मान भारत* स्वास्थ्य बीमा योजना को बंगाल की स्वास्थ्य साथी योजना के साथ रूपांतरित करके, 10 लाख रुपये के अधिक भार के साथ एक मजबूत *स्वास्थ्य बीमा योजना* के साथ बदल दिया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: भाजपा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में काफी गिरावट आई है

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि के तहत **₹2,298 करोड़** रुपये का फंड रोककर, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के करोड़ों लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत के **स्वास्थ्य देखभाल बजट** को 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.1% से घटाकर 2023 में केवल **0.35%** कर दिया है, जिससे हमारी भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतें गंभीर अनिश्चितता में डूब गई हैं
- कोई भी नागरिक उस परेशानी और निराशा को नहीं भूलेगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा **कोविड महामारी से सही प्रकार से नहीं निपटने के कारण** भारत की संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा गई थी, यहां के अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवा की कमी देखी गयी थी, इस दौरान अनगिनत विस्थापित प्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कई मौत के मामलों को छुपाए गए थे
- मोदी का **पीएम केयर्स फंड** भी एक भयावह विफलता रही है - इसमें पारदर्शिता की कमी, दोषपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति, और ऑडिट में चोरी की घटनाएं, भाजपा सरकार के इस फंड के दुरुपयोग के दुर्भावनापूर्ण इरादों को रेखांकित करती हैं
- आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे केंद्र सरकार की बेहद सफल बताया जा रहा है, विशिष्टता से प्रभावित है इसके **भेदभावपूर्ण पात्रता मानदंड** अधिकांश जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को दुर्गम बना दिया हैं
- CAG ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के **आयुष्मान भारत फंड** के कुप्रबंधन को उजागर किया है - 7.5 लाख लाभार्थियों को **फर्जी नंबरों** से जोड़ा गया, **मृत रोगियों** को भी ₹1.1 करोड़ का भुगतान किया गया, इस योजना के तहत 4,761 पंजीकरण सिर्फ 7 आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी ने बंगाल के लोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का बीड़ा उठाया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सभी की पहुंच में है

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित बजट 2010 में ₹3,442 करोड़ से **पांच गुना बढ़कर** 2024 में ₹20,053 करोड़ हो गया है
- बंगाल ने अपने क्रांतिकारी ***स्वास्थ्य साथी*** कार्यक्रम की मदद से सफलतापूर्वक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल किया है, जो प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की **मुफ्त स्वास्थ्य सेवा** प्रदान करता है
- 2011 के बाद से, बंगाल में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का व्यापक रूप से विस्तार किया गया है, जिसमें **42 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 329 अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं और 3,407 नर्सिंग होम चालू हैं**
- 2011 के बाद से, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 58,647 से बढ़कर 97,000 हो गई है, जबकि सरकारी डॉक्टरों की संख्या 2023 में **4,800 से तीन गुना बढ़कर 18,213 हो गई है**
- 2011 से 2020 तक बंगाल की आईएमआर 32 से गिरकर 19 **(40%)** और एमएमआर 117 से 103 **(12%)** हो गई; संस्थागत प्रसव 2011 में 68.1% से बढ़कर 2023 में 99.2% हो गया

अपनी स्थापना के बाद से, *सु-स्वास्थ्य केंद्रों* (एसएसके) ने 19 करोड़ रोगी इलाज के लिए पहुंचे हैं और यहां से **16 करोड़** बार रोगियों को **मुफ्त दवाएं** वितरित की गयी हैं.

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: आईएमआर और एमएमआर को कम करने पर जोर देने के साथ स्वास्थ्य सेवा के मानक को लगातार बेहतर करने का कार्य जारी रखेंगे

बंगाल के लिए

- **स्वास्थ्य सेवा में वर्क फोर्स को बढ़ावा देने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ में दो गुना वृद्धि की जाएगी।** रोगी देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सुधार करने के लिए, हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए पैरामेडिक्स के लिए सीटों की संख्या दोगुनी कर देंगे।

- **स्वास्थ्य सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए विशेष मोबाइल स्वास्थ्य वैन शुरु की जाएंगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं अंतिम छोर तक सभी के लिए पहुंच में रहें।

  हम नैदानिक परीक्षण, टीकाकरण, जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की डिलीवरी आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल स्वास्थ्य वैन लॉन्च करेंगे, ताकि नागरिक इन सेवाओं को अपने दरवाजे पर आसानी से प्राप्त कर सकें।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए अधिक डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन नीति बनाए जाएंगे।** टीएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि दूरदराज के इलाकों में डॉक्टरों की कमी अतीत की बात हो जाए।

  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की सिफारिशों के अनुरुप, हम ऐसी प्रतिनियुक्तियों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डॉक्टरों के लिए सुदुर क्षेत्रों में सेवा करने के लिए हार्डशिप और हाउसिंग एलाउंस में वृद्धि करेंगे।

- **स्वास्थ्य साथी योजना को बंगाल के प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्रवासी श्रमिक जहां भी हों, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलती रहे।

  हम स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ उन 28 लाख प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचाएंगे जो बंगाल के बाहर रहते हैं और काम करते हैं और जो कर्मसाथी परिजायी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं. प्रवासी श्रमिकों को बीमा कवरेज के माध्यम से अपने काम के स्थान पर स्थानीय अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी।

- **संक्रामक रोगों के इलाज के लिए उत्तर बंगाल में एक विशेष चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी।** टीएमसी संक्रामक रोगों का समय पर निदान और उपचार सुनिश्चित करेगी।

  हम संक्रामक रोगों के इलाज के लिए "इंफेक्सियस डीजीज एंड बेलियाघाटा जनरल हॉस्पिटल" के समान, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में एक समर्पित चिकित्सा संस्थान स्थापित करेंगे।

  संस्था रेबीज, खसरा, डेंगू, मलेरिया आदि संक्रामक रोगों के शीघ्र निदान, रोकथाम और उन्नत उपचार पर ध्यान केंद्रित करेगी।

देश के लिए

- **भारत का स्वास्थ्य देखभाल बजट जीडीपी का 5% तक बढ़ाया जाएगा।** टीएमसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च को तत्काल प्राथमिकता देगी।

  सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए, टीएमसी भविष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल बजट को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर जोर देगी, इसे डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के साथ संरेखित किया जाएगा।

  ऐसा करने से प्रमुख आवश्यकता वाले क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और एनीमिया से पीड़ित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध ग्रामीण गरीबों जैसे जोखिम वाले समुदायों तक पहुंच बढ़ाने पर अधिक खर्च करने में मदद मिलेगी।

- **मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को ₹10 लाख के कवर के साथ एक बेहतर स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम से बदल दिया जाएगा।** टीएमसी भारत के गरीबों और कमजोर लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करेगी।

  लोगों की रियायती माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए, हम मौजूदा जन आरोग्य योजना को बंगाल की प्रशंसित योजना की तर्ज पर पूरे देश के लिए स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम से बदल देंगे, जिससे प्रत्येक लाभार्थी के लिए बीमा कवर ₹5 लाख से दोगुना 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा।

  सभी 10 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें उपयुक्त सार्वजनिक या निजी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें पहले से मौजूद सभी चिकित्सा स्थितियों के लिए कवरेज भी शामिल है।

- **पीएम केयर्स फंड को आरटीआई और संसद के दायरे में लाया जाएगा।** टीएमसी पीएम केयर्स फंड की अंतहीन चोरी पर रोक लगाने के लिए ऑडिट करायेगी।

  इसे "पब्लिक अथॉरिटी" के रूप में वर्गीकृत करके, हम फंड को आरटीआई अधिनियम के तहत लाएंगे. इस पर निगरानी बढ़ाने के लिए, हम पीएम केयर्स को एक सार्वजनिक निधि के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेंगे और इसे लोक लेखा समिति के दायरे में लाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें प्रत्येक रुपया मजबूत, और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा।

- **मैत्री संपूर्ण पुष्टि पहल की शुरुआत की जाएगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके नवजात बच्चों पर बेहतर ध्यान दिया जाए।

  देश में आईएमआर और एमएमआर को कम करने के लिए, हम गरीब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मैत्री संपूर्ण पुष्टि पहल शुरू करेंगे, उन्हें पोषण किट प्रदान करेंगे. लाभार्थियों को दो पोषण किट और एक शिशु देखभाल आवश्यक किट प्राप्त होगी।






TAXI
TAXI





बुनियादी ढांचे का विकास, लोगोंके समृद्ध जीवन का आधार

मुख्य लक्ष्य

- सभी घरों को नल से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा
- सभी बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जो हर मौसम में यातायात के लिए उपयुक्त हो
- भारत और बंगाल के गरीबों को मानवाधिकारपूर्ण आवास प्रदान किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र ने बार-बार फंड आवंटन और बुनियादी ढांचे की विकास में बंगाल और अन्य राज्यों की उपेक्षा की है

- बंगाल में **11.3 लाख** लाभार्थियों को उनके सिर पर छत बनाने से वंचित कर दिया गया है. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ***आवास योजना*** के **₹8,140 करोड़ रोक दिए हैं**
- आवास की इस कमी के विनाशकारी प्रभाव दिखाई दिए हैं जलपाईगुड़ी तूफ़ान से हुई भारी क्षति में. यहां कई जानें गईं और आश्रय के अभाव में करीब 100 से अधिक लोग घायल हो गए
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के ग्रामीण विकास को ठप्प कर दिया है. सड़क कार्यों की मंजूरी में देरी हो रही है और **ग्राम सड़क योजना निधि** के **₹2,841 करोड़** को रोक दिया है
- ग्रामीण से लेकर शहरी नागरिक सुविधाओं तक, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने **अटल मिशन के ₹48 करोड़ रोककर** बंगाल में **ढांचागत विकास** को अवरुद्ध कर दिया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के घाटाल मास्टर प्लान के लिए एक भी रुपया मंजूर नहीं किया. जिस कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहना लगभग **17 लाख लोगों के जीवन और आजीविका को खतरे में डाल रहा है**
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की घोर अक्षमता है जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की **60% परियोजनाएँ रुक गईं या विलंबित हो गईं है**. जिसके कारण लागत में ₹4.7 लाख करोड़ की वृद्धि हुई
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एयर कनेक्टिविटी बढाने और आम लोगों की पहुंच में हवाई जहाज सफर करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही. भारी रियायतों के बावजूद भी **93% मार्ग उड़ान योजना** परिचालन को बनाए रखने में विफल रही है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की रेलवे के प्रति घोर लापरवाही, पुरानी बुनियादी ढांचे के कारण **244 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं** (2017 और 2022 के बीच) और 1 लाख से अधिक मौतें (2017 और 2021 के बीच).
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शहरी लोगों के सपने का स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने में विफल रही है. **400 परियोजनाओं के लिए 2023 की समय सीमा निर्धारित थी जिस पर ₹22,814 करोड़ खर्च होना था**
- **अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना** को प्रभावी ढंग से निर्धारित समय के अंदर पूरा करने में विफलता भाजपा सरकार की लगातार अतिवादिता का एक और उदाहरण है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी ने विकास के लिए एक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जिस पर हर बंगाली को गर्व हो सकता है

- अब तक **60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मजबूत आवास प्राप्त हुआ है**. जबकि स्थायी आवास के बिना **4 लाख चाय बागान श्रमिकों** को ***चा सुंदरी*** के तहत उनके सिर पर छत सुनिश्चित की जा रही है पथश्री के तहत, **26,487 किलोमीटर** सड़कों का **निर्माण और मरम्मत** की गई है, साथ ही अतिरिक्त **12,000 किलोमीटर** ग्रामीण सड़कें **निर्माणाधीन** हैं
- **59,916 स्कूलों, 43,866 आंगनबाड़ियों और 8,298 स्वास्थ्य केंद्रों** के लिए चालू जल आपूर्ति की

सुविधा के साथ-साथ **71.6 लाख ग्रामीण घरों** में नल जल कनेक्शन बढ़ाया गया है

बंगाल की स्थापित बिजली **क्षमता का आधार 2011 में 9,402.4 मेगावाट से 65% बढ़कर** 2023 में 15,529.77 मेगावाट हो गया

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: सुनिश्चित करेंगे कि पूरे भारत और बंगाल में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना जारी रहे

बंगाल के लिए

- **बंगाल के गरीबों को गारंटीशुदा आवास मुहैया कराया जाएगा।** केंद्र के समर्थन के साथ या उसके बिना, टीएमसी हर पात्र परिवार के सिर पर छत सुनिश्चित करेगी।

  बंगाल में गरीबों के लिए मकानों की फंडिंग से भाजपा सरकार के इनकार को देखते हुए, हम स्वतंत्र रूप से सभी पात्र लाभार्थियों के लिए 11.2 लाख मकान बनाएंगे, जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तपोषित होंगे. अगले चरण में अतिरिक्त 5.8 लाख घर बनाए जाएंगे।

- सभी घरों में **24×7 कार्यात्मक नल जल कनेक्शन** प्रदान किया जाएगा। टीएमसी अतिरिक्त 1 करोड़ घरों को पाइप से पीने पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे राज्य भर में 100% स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल कवरेज सुनिश्चित होगी।

- **बंगाल की सभी बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे बंगाल में गुणवत्तापूर्ण सड़कों तक पहुंच हो। पथश्री-3 के माध्यम से, हम अपनी सड़क नवीनीकरण और विस्तार पहल के दो पिछले पुनरावृत्तियों को वहीं जारी रखेंगे जहां हमने छोड़ा था और **12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण** करके ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे।

- **कोलकाता मेट्रो को और आगे बढ़ाया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि कोलकाता के सभी नागरिक शहर के किसी भी कोने से तेज, किफायती और आरामदायक परिवहन का उपयोग करके यात्रा कर सकें।

  हम मौजूदा कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में कुल **11.5 किमी की दूरी जोड़ेंगे**, ताकि मेट्रो लाइन कोलकाता के हर कोने तक पहुंच सके और अधिकतम उपनगरीय क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से कवर कर सके।

देश के लिए

- **भारत के गरीबों के लिए सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जाएगा।** टीएमसी हर गरीब परिवार के सिर पर छत लाने का प्रयास करेगी।

  नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, नए लाभार्थियों के लिए आवास योजना के आवेदनों को तेजी से मंजूरी देकर, और आवास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं में तेजी लाकर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों के लिए आवास का प्रावधान तेज गति से हो, ताकि सम्मानजनक आवास का सपना पूरा हो सके. यह पहले की तुलना में भारत के सभी गरीबों के लिए अधिक शीघ्रता से वास्तविकता बन सकता है।

- **भारत के रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों के अनुकूल रहते हुए भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाए।

  यात्रियों की भारी संख्या और पुराने बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम भारत की रेलवे को अवलोकन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

  - यात्री सुरक्षा में सुधार के लिए ट्रैक मार्गों पर ट्रेन इंजनों और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों पर टक्कर-रोधी तकनीक की स्थापना
  - माल ढुलाई और यात्री यातायात को अलग करने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के पूरा होने में तेजी लाना जिससे माल और यात्री रेल गाड़ियों दोनों की गति और विश्वसनीयता बढ़ेगी
  - टिकट बुक करने के लिए अधिक संवेदनशील उपयोगकर्ता अनुभव को सक्षम करने के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के वेब आर्किटेक्चर में वृद्धि, बार-बार वेबसाइट क्रैश होने या बुकिंग विफलता को अतीत की बात बना दिया जाएगा
  - यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए टिकटिंग, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ग्राहक सेवा के लिए डिजिटल और ऐप-आधारित समाधानों का कार्यान्वयन

- **रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाएगा.** टीएमसी भारत के सबसे बड़े यात्री तंत्रों में से एक के लिए उचित बजटीय फोकस सुनिश्चित करेगी।

  हम भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे, परिचालन और वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए रेलवे के लिए एक अलग बजट बहाल करेंगे। हम 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती किरायों को फिर से शुरू करने के लिए उपयुक्त मानदंड भी स्थापित करेंगे।

- **बंदरगाह विकास और बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।** टीएमसी भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए विकास के त्वरित इंजन के रूप में बंदरगाहों का उपयोग करेगी।

  हम आर्थिक और औद्योगिक विकास में बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण के प्रतिमान को सर्वोपरि महत्व देंगे।

  प्रयास किये जायेंगे:

  - मौजूदा बंदरगाह बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करें, जैसे क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए कार्गो हैंडलिंग उपकरणों को अपग्रेड करना और बंदरगाहों पर व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए परमिट और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना
  - अधिक तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) को अधिसूचित करें) और प्रमुख गहरे पानी के बंदरगाहों के आसपास संपन्न औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल परिवहन समाधान जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास
  - बेहतर सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के माध्यम से बंदरगाहों और मुख्य भूमि क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार

- **भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड को मजबूत करने के उपाय किये जायेंगे.** बिजली आपूर्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए टीएमसी देश के पावर ग्रिड को व्यवस्थित रूप से मजबूत करेगी.

  भारत के पावर ग्रिड पर महत्वपूर्ण वार्षिक तनाव को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से देश में गर्मी के महीनों के दौरान, अधिक लचीला ग्रिड विकसित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे, जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

  - आपूर्ति की कमी को संबोधित करना, विशेष रूप से थर्मल पावर प्लांट जैसे पारंपरिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों में
  - ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को कम करने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाकर ट्रांसमिशन

बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

- गर्मी की वेब/या तूफान जैसे अन्य आपदा परिदृश्यों के सामने पावर ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों का एकीकरण और ग्रिड स्वचालन को बढ़ाया जाएगा
- वर्तमान भंडारण और वितरण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर पावर ग्रिड में अधिक ग्रीन हाइड्रोजन का एकीकरण किया जाएगा







राष्ट्रीय सुरक्षाको सुनिश्चित करना, है प्रतिबद्धता हमारा

मुख्य लक्ष्य

- भारत की राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा यांत्रिकी को प्रभावी रूप से मजबूत किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: घरेलू स्तर पर तमाम दिखावे के बावजूद, केंद्र सरकार सुरक्षा खतरों से निपटने में विफल रही है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा **बीएसएफ** के मनमाने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के कारण बंगाल के कई निर्दोष लोगों की अन्यायपूर्ण हत्याएं हुई हैं. सुरक्षा के बजाय बंगाल के लोग बीएसएफ के अत्याचारों का शिकार बने
- **पुलवामा हमले** में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान लेने वाले घातक हमले के लगभग 6 साल बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जांच के नतीजे अपारदर्शी और अनिर्णायक बने हुए हैं
- 2020 में गलवान में चीनी घुसपैठ में भारत और चीन के बीच दशकों में पहली खूनी झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप **20 लोग हताहत हुए.** सीमा पर चीनी बुनियादी ढांचे के जारी निर्माण को रोकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही
- पीएम मोदी की बेतुकी बयानबाजी और उदासीन रवैए के बीच, चीन ने डोकलाम में अपना सैन्य और बुनियादी ढांचा निर्माण जारी रखा है, जिससे **सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा** और पूर्वोत्तर के लिए भारतीय मुख्य भूमि की कनेक्टिविटी खतरे में पड़ गई है
- **21** दौर की उच्च-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में 2,000 किमी भारतीय क्षेत्र पर साहसपूर्वक कब्जा करना जारी रखा है, जिससे हमारी सेना को हमारी 65 गश्त चौकियों में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोकाचार की अवहेलना की है और आरएसएस, हिंदुत्व समूहों और भाजपा नेताओं से जुड़े निजी शैक्षणिक संस्थानों को **40 सैनीफी स्कूल एग्रीमेंट** देकर अपने सहयोगियों के खजाने को भरने के लिए हमारे सशस्त्र बलों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है
- केंद्र सरकार की विचारहीन **अग्निपथ योजना** ने भारतीय सशस्त्र बलों की व्यावसायिकता को कमजोर कर दिया है और अनगिनत युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: यह सुनिश्चित करना कि भारत की सुरक्षा क्षमताओं को प्रभावित करने वाली कमजोरियों को सर्जिकल एलिमेंट द्वारा समाप्त कर दिया जाए

बंगाल के लिए

- **बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से 15 किमी तक सीमित हो जाएगा।** टीएमसी बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

  हम सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक अधिकार क्षेत्र को बंगाल की सीमा पर मौजूदा 50 किमी से 15 किमी की पिछली सीमा तक समायोजित करने के लिए बीएसएफ अधिनियम, 1968 में उपयुक्त संशोधन करेंगे।

- **राज्य में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाई जाएगी**। टीएमसी विदेशी घुसपैठियों से राज्य और देश की रक्षा करेगी.
  हम राज्य में सीमा पार विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे।

- **सीमा पर प्रमुख रणनीतिक स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियां स्थापित किए जाएंगे.** ड्रोन का उपयोग करके सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे. कनेक्टिविटी और निगरानी में सुधार के लिए सीमावर्ती गांवों में सड़कों का निर्माण।

देश के लिए

- **भारत की राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी रूप से मजबूत किया जाएगा।** भारतीय सुरक्षा और सुरक्षा को सुधारने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। हम वर्तमान बीएसएफ अधिनियम को संशोधित करेंगे ताकि शांतिकाल में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बल के दुरुपयोग के आरोपों की त्वरित जाँच के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण समिति की स्थापना की जाए।

- **अग्निपथ योजना।** हम भारतीय सशस्त्र सेना के पारंपरिक भर्ती तंत्र को पुनः स्थापित करेंगे।




নাম্বারি
তাওয়া



महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण, बनाना है उन्हें स्वावलंबी

मुख्य लक्ष्य

- लक्ष्मीर भंडार योजना को क्रांतिकारी रूप से मजबूत किया जाएगा, जिसमें सामान्य महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को प्रति माह ₹1,200 (वार्षिक ₹14,400) मिलेगा और यह देश भर में लागू किया जाएगा ।

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र की निगरानी में महिलाओं की सुरक्षा एक दुःस्वप्न बनकर रह गई है

- पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने बंगाल के हर राजनीतिक दौरे के दौरान देश की एकमात्र महिला सीएम ममता बनर्जी का लगातार **मजाक उड़ाया, अपमान किया और उन्हें बुरा-भला कहा**
- टीएमसी महिला नेताओं को दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के हाथों **क्रूर दुर्व्यवहार** का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा रोके गए पश्चिम बंगाल के वाजिब बकाए की जमकर मांग की
- भाजपा शासन के तहत, हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2014 के बाद से **31% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है**
- बार-बार, राष्ट्र की सामूहिक चेतना को **बलात्कार के दिल दहला देने वाले मामलों** से झकझोर दिया गया है, जैसा कि **कठुआ, उन्नाव और हाथरस** में देखा गया - नाबालिग या वयस्क, दलित या उच्च जाति, कोई भी महिला भाजपा के भारत में सुरक्षित नहीं है
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत **127/146 देशों** में है - यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में हम कितने पीछे रह गए हैं
- भारत की महिलाओं को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कभी माफ नहीं करना चाहिए कि कैसे उन्होंने सांसद बृजभूषण के खिलाफ न्याय की गुहार को नजरअंदाज करके, उन्हें अपमानजनक रूप से गिरफ्तार करके और मीडिया में उन्हें बदनाम करके **हमारी महिला पहलवानों, हमारे देश का गौरव, को अपमानित किया**
- महिलाओं की सुरक्षा और दुर्दशा के प्रति भाजपा की उदासीनता इस तथ्य से स्पष्ट है कि **निर्भया फंड का 30% अप्रयुक्त है**
- मणिपुर में एक शातिर भीड़ द्वारा दो एसटी महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने के भयानक दृश्य भाजपा के भारत में महिलाओं के खिलाफ आतंक और अत्याचार के शासन को दर्शाते हैं
- भयावह **"बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले"** में 11 दोषियों को छूट देने से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की निगरानी में यौन अपराधियों को छूट देने की एक बुरी मिसाल कायम हुई है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की बेजोड़ विरासत है

- इसके माध्यम से **2 करोड़** से अधिक महिलाओं का उत्थान और आर्थिक रूप से सशक्तीकरण किया गया है. ***लक्ष्मी भंडार योजना*** है
- **लगातार तीसरे वर्ष, कोलकाता** को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा **भारत का सबसे सुरक्षित शहर** घोषित किया गया है
- 2024-25 में बंगाल के राज्य विकास बजट (एसडीबी) का **44%** महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए आवंटित किया गया है
- जय बांग्ला पेंशन योजना के तहत, 11.65 लाख महिलाओं को **वृद्धावस्था पेंशन** प्राप्त हुई है, 20 लाख महिलाओं को **विधवा पेंशन** से लाभ हुआ है, **जिससे कमजोर महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की गई है**

एसएचजी को ऋण देने में बंगाल देश का **शीर्ष राज्य** है, जहां 11 लाख से अधिक एसएचजी सफलतापूर्वक ऋण से जुड़े हुए हैं, आश्चर्यजनक रूप से **₹90,000 करोड़** का बैंक ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है

- भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री और निवर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों के दूसरे सबसे बड़े पार्टी प्रतिनिधित्व के साथ, **बंगाल ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गति निर्धारित की है**। इसने 18 वीं लोकसभा चुनावों में 28% महिला उम्मीदवारों को नामांकित करके एक समान मिसाल कायम की है
- **पीआरआई में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है**; निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 2008 में 21,351 से बढ़कर 2023 में 30,458 हो गई है.
- **महिला सुरक्षा को सबसे आगे रखते हुए**, हमारी महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए राज्य में 49 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं.

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: प्रत्येक भारतीय महिला की सुरक्षा, गरिमा और एजेंसी को बहाल करना

बंगाल के लिए

- **क्रांतिकारी लक्ष्मी भंडार योजना को और मजबूत किया जाएगा।** टीएमसी बंगाल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जारी रखेगी।

  कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दिया गया है। सामान्य महिलाओं के लिए, और ₹1,200 प्रति माह तक एससी/एसटी महिलाओं के लिए। इसे सभी 2.1 करोड़ लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पहुंचाया जाता रहेगा।

- **राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।** टीएमसी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपनी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित परंपरा को औपचारिक रूप देगी।

  हम अपने राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को औपचारिक रूप से अपनाएंगे और, जैसा कि पहले हुआ था, अपने राज्य में सभी स्तरों पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय करना जारी रखेंगे।

- **पूरे बंगाल में जिला स्तरीय एसएचजी बाज़ार स्थापित किए जाएंगे।** टीएमसी एसएचजी को राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिक मजबूती से भाग लेने में मदद करेगी। अपने एसएचजी को अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से एकीकृत करने के लिए हम प्रत्येक जिले में समर्पित बाज़ार स्थापित करेंगे जहां वे बिक्री के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें।

- **राज्य पुलिस में अधिक महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।** महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार के लिए टीएमसी अपने पुलिस बल में विविधता लाएगी।

  हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 12 महीनों के भीतर बंगाल में सभी मौजूदा पुलिस रिक्तियों में से कम से कम 33% प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा भरी जाएं। ऐसे कुल स्टेशनों की संख्या 65 तक ले जाने के लिए राज्य भर में 16 अतिरिक्त केवल महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे।

- **महिलाओं को आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया जाएगा।** टीएमसी बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मौजूदा हेल्पलाइन नंबर 1091 के साथ 'सुरक्षा' ऐप पेश किया जाएगा।

  यह ऐप महिलाओं को आपात स्थिति में एसओएस अलर्ट जारी करने और उन्हें तेजी से नजदीकी पुलिस गश्ती दल से जोड़ने की सुविधा देगा। हम ऐप के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र भी चलाएंगे।

देश के लिए

- **प्रत्येक घर की महिला मुखिया को ₹1,000 प्रति माह की गारंटीकृत, बिना शर्त आय प्रदान की जाएगी।** भारत की बढ़ती आय असमानताओं को पाटने में मदद करने के लिए टीएमसी हर गरीब परिवार को बुनियादी आय का आश्वासन देगी।

  बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की सफलता से सीखते हुए, हम भारत में सभी परिवारों को ₹1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जो प्रभावी रूप से उनकी वार्षिक आय में ₹12,000 की राशि का पूरक होगा।

  यह राशि हर नामांकित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को हर महीने डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी. सार्वभौमीकरण प्राप्त करने के इरादे से, इस योजना को धीरे-धीरे समय के साथ पूरे भारत में महिलाओं की बढ़ती संख्या तक विस्तारित किया जाएगा।

- **कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या असमानता को कम करने के लिए बनाए गए मौजूदा कानूनों और कृत्यों की समीक्षा की जाएगी।** टीएमसी भारत के कार्यस्थलों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी।

  हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने के लिए बनाए गए सभी कृत्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और विधिवत संशोधित किया जाए. विशेष रूप से, कारखाना अधिनियम (1948), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) के प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाएगा और बाद में कार्यस्थल में महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए आधुनिकीकरण किया जाएगा।

- **हर जिले में फास्ट-ट्रेक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।** टीएमसी समर्पित, फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से महिलाओं के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगी।

  महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बैकलॉग से निपटने के लिए, हम भारत के प्रत्येक जिले में 1, 766 फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगे. उन्हें न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों और यौन अपराधों से लेकर बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के मामलों में।

- **महिलाओं को वर्कफोर्स में पुनः शामिल करने के लिए एक नई नीति स्थापित की जाएगी।** टीएमसी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली महिलाओं के लिए श्रम बल में दोबारा प्रवेश को आसान बनाने के लिए कदम उठाएगी।

  भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए, हम उन लाखों महिलाओं के लिए एक नई नीति पेश करेंगे जो गर्भावस्था, विवाह या अन्य सामाजिक-आर्थिक दबावों के परिणामस्वरूप समय से पहले कार्यबल से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं।
  इस नीति के प्रमुख घटक होंगे:

  - उन महिलाओं के लिए अंशकालिक कार्य नीति जो सहायक शिशु देखभाल कर्तव्यों के कारण पूर्णकालिक काम करने में असमर्थ हैं
  - महिलाओं के लिए ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए मौजूदा कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रीस्किलिंग कार्यक्रम शुरू करना
  - बड़ी कंपनियों (1,000 से अधिक श्रमिकों) के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई), काम पर रखे गए और बरकरार रखी गई महिला श्रमिकों के अनुपात के आधार पर होगा।

- **भरतीय महिला बैंक को पुनर्जीवित किया जाएगा।** टीएमसी महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं और ऋण तक पहुंच बढ़ाएगी।

  हम पूर्ववर्ती भारतीय महिला बैंक को फिर से स्थापित करेंगे, जिसे 2017 में एसबीआई की सहायक कंपनी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था, इसकी प्रारंभिक पूंजी के साथ इसकी स्थापना शर्तों के अनुसार 1000 करोड़ होगा. भारत भर में 800 शाखाएँ स्थापित करने की मूल योजना को पटरी पर लाया जाएगा, जिससे बैंक महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करने और लिंग के आधार पर अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित करेगा।



महिला सशक्तिकरण







युवाओं का सशक्तीकरण, उज्ज्वल भविष्यका सुनीसिचितकरण

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल में वार्षिक राज्यस्तरीय खेल प्रतिभा खोज आयोजित की जाएगी
- भारत के शिक्षित युवा को उनकी रोजगारी को बढ़ाने के लिए पेशेवर 1 वर्षीय अपरेंटिसशिप प्रदान की जाएगी
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र ने भारत के महत्वाकांक्षी युवाओं की असीम क्षमता को बर्बाद कर दिया है.

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे के विपरीत, **2022 में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है.** भारत में अभूतपूर्व बेरोजगारी देखी गई है, **इसमें से 83% हमारे युवाओं में है,** जिससे हमारे लोगों की आशाएं और सपने चकनाचूर हो गए हैं
- बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बावजूद, केंद्र में आश्चर्यजनक रूप से **10 लाख सरकारी पद** खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की **कोई योजना नजर नहीं आ रही है**
- 2017-18 और 2022-23 के बीच, स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 19.2% से बढ़कर **35.8%** और स्नातकोत्तरों के बीच 21.3% से **36.2%** तक बढ़ गई है, जो देश में कुशल नौकरियों की आश्चर्यजनक कमी को उजागर करती है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बहुप्रचारित "स्किल इंडिया" कार्यक्रम बुरी तरह विफल हो गया है - *प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना* के तहत प्रशिक्षित **1.4 करोड़ युवाओं में से 80% बेरोजगार हो गए हैं,** जिससे उनके उज्जवल भविष्य की आकांक्षाएं चकनाचूर हो गई हैं

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: नौकरियों और उन्नयन पर टीएमसी सरकार का ध्यान हमारे युवाओं की क्षमता को उजागर कर रहा है

- बंगाल ने 13 वर्षों में **₹11.5 लाख करोड़ का निवेश** आकर्षित किया है, जिससे **1.3 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां पैदा हुई हैं**
- आईटीआई का वार्षिक प्रवेश **तीन गुना बढ़ गया है,** जो 2011 में 80 आईटीआई में 16,715 से बढ़कर वर्तमान में 48,201 हो गया है, जो राज्य में 298 आईटीआई में फैला हुआ है.
- सूचना सोसायटी पर संयुक्त राष्ट्र-विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) 2019 से सम्मानित योजना उत्कर्ष बांग्ला ने **35.4 लाख युवाओं** को अल्पकालिक कौशल विकास सहायता प्रदान की है
- *'युवाश्री'* ने नौकरी चाहने वालों को मासिक **वजीफा ₹1,500** (वार्षिक ₹18,000) प्रदान किया जाता है, जिससे अब तक कुल मिलाकर लगभग 2 लाख युवा लाभान्वित हुए हैं.

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: कार्य क्षेत्र और खेल दोनों फिलाड में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण होगा

बंगाल के लिए

- **वार्षिक राज्यव्यापी खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा।** टीएमसी बंगाल की समृद्ध खेल विरासत को बढ़ावा देना और बनाए रखना जारी रखेगी. हम संभावित युवा एथलीटों की पहचान करने,उनकी प्रतिभा का पोषण करने

और युवाओं के बीच खेलों में सामान्य खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यव्यापी खेलों का आयोजन करके बंगाल के युवाओं को उनके खेल जुनून के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ने में मदद करेंगे।

- कार्यक्रम क्रमिक रूप से 5 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा जिनमें गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य शामिल होंगे
- 4 खेलों फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, कबडडी का आयोजन किया जायेगा।
- प्रत्येक वर्ष के टैलेंट हंट के दौरान खोजी गई शीर्ष प्रतिभाओं को पेशेवर रूप से खेलने और राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल और वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से राज्य-प्रायोजित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही राज्य के पंचायत-स्तरीय कैडर के भीतर एक गारंटीकृत नौकरी भी प्रदान की जाएगी।

- **छात्रों के लिए सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के अवसर पैदा किये जायेंगे।** हम 'युवाशक्ति' नामक एक नई योजना शुरू करेंगे, जिसमें सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने और बंगाल में शासन प्रक्रियाओं का वास्तविक दृश्य प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का लंबा अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकारी विभागों में कुल 10,000 ऐसी इंटर्नशिप बनाई जाएंगी और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रदान की जाएंगी. इंटर्नशिप पूरा करने वाले छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

- **बंगाल का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।** टीएमसी खेल विकास और प्रदर्शन में अग्रणी राज्य के रूप में बंगाल की स्थिति को बढ़ावा देगी।

  हम बंगाल और भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्नत प्रशिक्षण, शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए हुगली के चिनसुराह में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करेंगे।

- **ला लीगा के साथ साझेदारी में एक विश्व स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी।** टीएमसी बंगाल में फुटबॉल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाएगी।

  हम बंगाल की फुटबॉल प्रतिभा को पोषित करने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर सफल होने के लिए तैयार करने के लिए स्पेन की प्रमुख घरेलू फुटबॉल लीग, ला लीगा के साथ साझेदारी में किशोर भारती क्रीडांगन में एक अत्याधुनिक फुटबॉल अकादमी स्थापित करेंगे।

- **सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा।** टीएमसी उत्तर बंगाल में खेल सुविधाएं बढ़ाएगी और खेल प्रतिभाओं को पोषित करेगी।

  हम खेल के स्तर को उन्नत करेंगे, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएंगे और स्टेडियम में मौजूदा छात्रावास के बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे. ये संवर्द्धन न केवल एथलीटों और आगंतुकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे बल्कि पूरे उत्तर बंगाल क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे।

देश के लिए

- **भारत के शिक्षित युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पेशेवर 1-वर्षीय प्रशिक्षुता प्रदान की जाएगी।** टीएमसी भारत के युवाओं को नौकरी बाजार के लिए तैयार होने में सहायता करेगी।

  भारत के शिक्षित युवाओं को पेशेवर बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ऐसे कौशल हासिल करने में सक्षम हैं जो उन्हें रोजगार सुरक्षित करने और उसमें आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं, हम 25 वर्ष की आयु के बीच के सभी डिप्लोमा धारकों या कॉलेज स्नातकों को 1 साल की गारंटीकृत प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नया राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेंगे।

40, सफल प्रशिक्षुओं के लिए सुनिश्चित कौशल विकास और भविष्य में पूर्णकालिक रोजगार की संभावनाओं के साथ. युवाओं को आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करने में सक्षम बनाने और एक बार नामांकित होने के बाद कौशल-विकास पाठ्यक्रमों में बने रहने के लिए अधिक दृढ़ता से प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें एक उपयुक्त मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा, ताकि वे "सीखने के साथ-साथ कमा सकें"।

- **उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।** टीएमसी भारत के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और अधिक किफायती बनाएगी।

  भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्र क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% की रियायती ब्याज पर 10 लाख तक का क्रेडिट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- **सरकारी नौकरियों में मौजूदा 10 लाख रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दी जाएगी।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि नौकरियों के लिए भारतीय युवाओं की मांग का जवाब दिया जाए।

  सरकार बनने पर, हम देरी-मुक्त प्रक्रिया स्थापित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के उद्देश्य से, देश भर में रिक्तियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सभी केंद्रीय सरकारी विभागों की व्यापक रिक्ति ऑडिट करेंगे।

  इन चरणों के आधार पर, एक व्यापक नौकरी कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विभाग या सार्वजनिक निकाय की रिक्तियों को भरने के लिए स्पष्ट समयसीमा होगी. इसके बाद हम इस प्रक्रिया को एक वार्षिक घटना के रूप में संस्थागत रूप देंगे।

- **भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण ढांचे को मजबूती से आधुनिक बनाया जाएगा।** कौशल भारत की व्यापक अपर्याप्तताओं से सीखते हुए, टीएमसी भारत में कौशल विकास के भविष्य के लिए अधिक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, उद्योग से जुड़े, भविष्य-प्रूफ व्यावसायिक शिक्षा ढांचे को बढ़ावा देगी।

  इस ढांचे में शामिल होंगे:

  - कौशल विकास का एक '60:40' मॉडल - कक्षा में 60% पाठ्यचर्या संबंधी शिक्षा, फैक्ट्री फ्लोर पर 40% ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण द्वारा पूरक होगा
  - शिक्षकों के कौशल को बढ़ाकर और अधिक उद्योग-अकादमिक संबंधों के माध्यम से शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों को क्रॉस-लर्निंग के अवसर प्रदान करके प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया गया
  - वैश्विक उद्योग दिग्गजों के सहयोग से विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल प्रमाणन कार्यक्रम डिजाइन (और लगातार अद्यतन) किए जाएंगे
  - एआई, एमएल, सेमीकंडक्टर घटक निर्माण आदि जैसे उभरते उद्योगों से संबंधित कौशल में युवाओं (हाशिये पर रहने वाले समुदायों सहित) को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम होगा

- **पूरे भारत में अत्याधुनिक खेल अकादमियां बनाई जाएंगी।** टीएमसी भारत की खेल प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करेगी।

  हमारे देश की विशाल आबादी में खेल प्रतिभा के स्तर को खोजने, पोषित करने और पूरी तरह से विकसित करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश भर में विश्व स्तरीय खेल "उत्कृष्टता केंद्र" विकसित किए जाएं, जो प्रतिभा आधारित पहचान और प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र की खेल परंपराओं पर होगा।

  ये आधुनिक बुनियादी ढांचे (खेल की स्तर, इनडोर/आउटडोर अभ्यास सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं) के साथ-साथ खेल विज्ञान, पोषण केंद्र आदि जैसी आधुनिक क्षमताओं से सुसज्जित होंगे।



11



अल्पसंख्यक और बुतपरस्त, आइए मिलकर आगे बढ़ें

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल की विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रहेगा
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को समाप्त किया जाएगा, और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को बंद किया जाएगा
- संघीय नागरिक संहिता (यूसीसी) को भारत में लागू नहीं किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र भारत को अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने **बंगाल के समुदायों के साथ वस्तुओं** जैसा व्यवहार किया है - राजबंशियों की सीएपीएफ नारायणी सेना बटालियन की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है, 11 गोरखा उप-जनजातियां एक दशक से एसटी दर्जे का इंतजार कर रही हैं, और नागरिकता के अस्पष्ट वादों से मतुआओं को लगातार धोखा दिया जा रहा है

- मतुआ समुदाय के उत्थान के लिए दावा करने के बावजूद, राम मंदिर भूमि पूजन के लिए **उनके द्वारा भेजी गई मिट्टी को अस्वीकार** करना भाजपा के अंतर्निहित जातिवाद को उजागर करता है

- *'सबका साथ, सबका विकास'* से दूर, भाजपा सरकार ने **2023-24 में** अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में **38%** की कटौती की

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत, हाशिए पर रहने वालों का जीवन पूरी तरह से आतंक की स्थिति में आ गया है. 2014 से 2022 तक, **अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार में 42.5% की वृद्धि हुई है, और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार में 47% की वृद्धि हुई है**

- मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक को अपमानित करने का भाजपा कार्यकर्ताओं का घिनौना कृत्य, हाथरस में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, और मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की परेड के वीभत्स दृश्य भाजपा शासित राज्यों में **इन समुदायों द्वारा अनुभव की गई गरिमा की गिरावट को दर्शाते हैं**

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने घोर असंवैधानिक **सीएए** लाकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया है और उनके अधिकार छीन लिये हैं. 2024 के चुनावों से पहले अधिनियम के निंदनीय कार्यान्वयन ने उनकी नापाक विभाजनकारी राजनीति और भेदभाव को उजागर कर दिया है.

- भाजपा ने घरों और मदरसों पर बुलडोजर चलाकर, **हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि, नफरत भरे भाषण और धार्मिक अल्पसंख्यकों की लिंचिंग के माध्यम से भय,** धमकी और गैरजिम्मेदारी का 'राज्य-प्रायोजित' माहौल बनाया है.

- उच्च शिक्षण संस्थानों में **एससी/एसटी नामांकन समग्र राष्ट्रीय औसत से नीचे गिर गया है,** जो समान पहुंच में भारी असमानता को दर्शाता है. पिछले 5 वर्षों में, 13,626 एससी, एसटी और ओबीसी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से बाहर हो गए हैं.

मां-माटी-मानुष की सरकार ने क्या किया: बंगाल में हाशिये पर पड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाया और उत्थान किया गया है

- बंगाल की एससी/एसटी महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए, *लक्ष्मी भंडार* के तहत मासिक वित्तीय सहायता **₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,200 कर दी गई है**

- राज्य में एससी/एसटी समुदायों से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, नेताओं और सुधारकों की विरासत का सम्मान करने के लिए **कूच बिहार थफीउर पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, हरिचंद-गुरुचंद विश्वविद्यालय**

और कबी साधु रामचंद मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई हैकुरमाली, राजबंशी और संथाली आदि भाषाओं की आधिकारिक मान्यता भाषाई विविधता और समावेशिता के प्रति बंगाल के समर्पण के प्रमाण के रूप में कार्य करती है

- बंगाल की राज्य **विधानसभा ने सारी और सरना धर्मों की आधिकारिक** मान्यता के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जो विविध धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने के लिए हमारे राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है
- आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को संरक्षित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत **48,953 निजी पट्टे और 851 सामुदायिक पट्टे** जारी किए गए हैं
- पहाड़ी जनजातियों और अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बंगाल में **7 विकास और सांस्कृतिक बोर्ड** स्थापित किए गए हैं
- ₹800 प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता शिक्षाश्री योजना के माध्यम से कक्षा V-VIII तक के **1.15 करोड़ एससी/एसटी छात्रों** को प्रदान किया जा रहा है
- किसी भी राज्य ने बंगाल जितनी **अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां** नहीं दी हैं - **3.4 करोड़** से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को हमारी सरकार *ऐक्यश्री* और अन्य छात्रवृत्तियों के तहत समर्थन दे रही है जो पूरे देश में सबसे अधिक है
- ***तपोसिलि बंधु योजना*** के तहत वृद्धावस्था पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह लगभग 11 लाख अनुसूचित जाति को प्रदान किया जाता है
- ***जय जोहार योजना*** के तहत वृद्धावस्था पेंशन ₹1,000 प्रतिमाह 3 लाख से अधिक एसटी को प्रदान किया जाता है

टीएमसी ने क्या करने का संकल्प लिया है: सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत के हाशिये पर पड़े लोगों की इच्छाओं और मांगों को एक बार फिर शासन के केंद्र में रखा जाए

बंगाल के लिए

- **राजबंशी समुदाय के हितों को मान्यता देने के लिए सीएपीएफ के तहत एक नारायणी सेना बटालियन का गठन किया जाएगा।** टीएमसी उत्तर बंगाल में राजबंशी समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेगी।

  इतिहास को श्रद्धांजलि देने और नारायणी सेना के योद्धाओं और कूचबिहार के राजबंशियों की वीरता को याद करने के लिए, हम एक नई सीएपीएफ नारायणी सेना बटालियन के गठन के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार करेंगे।

- **गैर-मान्यता प्राप्त समुदायों के लिए ओबीसी स्थिति का मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।** टीएमसी ओबीसी सूची से बाहर रह गए समुदायों की राजनीतिक और सामाजिक मान्यता सुनिश्चित करेगी।

  हम उन सभी समुदायों को ओबीसी दर्जा देने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे, जिन्हें मंडल आयोग द्वारा ओबीसी दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे महिस्या, तिली, तामुल, सहस, आदि। इसका प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा होने पर, हम तुरंत इन

समुदायों को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करेंगे. इसके बाद हम इन समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में भी शीघ्र शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ जुड़ेंगे।

- **सारी और सरना आदिवासी धर्मों के लिए धार्मिक कोड स्थापित किये जायेंगे।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि स्वदेशी और आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित इन प्राचीन आस्थाओं को आधिकारिक तौर पर विशिष्ट धार्मिक संप्रदायों के रूप में स्वीकार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्वदेशी धर्मों के अनुयायियों को अपनी धार्मिक पहचान का पालन करने का मौलिक अधिकार है, हम सारी और सरना के लिए अलग धार्मिक कोड सुरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ जुड़ेंगे।

- **11 गोरखा उप-समुदायों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि गोरखाओं की मान्यता और उत्थान की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो।

  गोरखाओं के 11 उप-समूहों - भुजेल, गुरुंग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राय को शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे। सुनुवर, थामी, यक्का (दीवान), और धिमल समुदाय एसटी सूची में।
  महतो समाज को एसटी का दर्जा दिया जायेगा. टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि समुदाय की अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उत्थान की मांग पूरी हो।

  बंगाल की महतो आबादी की गणना के लिए चल रहे सर्वेक्षण के पूरा होने पर, हम जल्द से जल्द राज्य स्तर पर एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और उसे मंजूरी देंगे. हम यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ जुड़ेंगे कि महतो को एसटी का दर्जा देने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाए।

देश के लिए

- **नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को खत्म कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को बंद कर दिया जाएगा।** टीएमसी प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाजपा की फूट डालो और राज करो की नीतियों से बचाने के लिए जोरदार संघर्ष करेगी।

  हम लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे और आधिकारिक तौर पर सीएए को निरस्त करने की मांग करेंगे। सरकार बनने पर, हम तुरंत एनआरसी को बंद करने और सभी हिरासत शिविरों को स्थायी रूप से बंद करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी करेंगे।

- **समान नागरिक संहिता को हकीकत नहीं बनने दिया जाएगा।** टीएमसी संविधान के अनुसार भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को संरक्षित करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी।

  हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारत के लिए समान नागरिक संहिता अपनाने वाले किसी भी विधेयक का सर्वसम्मति से विरोध करेंगे. अन्य वैचारिक रूप से गठबंधन वाली पार्टियों के सहयोग से, हम इसके पारित होने को रोकने में सक्षम एक वोटिंग ब्लॉक को एकजुट करेंगे।

- **सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू किया जाएगा।** टीएमसी भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करेगी।

  हम राज्य और निजी क्षेत्र की नीतियों की निगरानी करने और वंचित समूहों के लिए शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान अवसर आयोग की स्थापना करेंगे।







बंगाल ने आज, बनाया है एक सुरक्षित नया समाज

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल में और अधिक एमएए कैंटीन्स स्थापित किए जाएंगे,
- मध्याह्न भोजन के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाएगा
- भारत के 60 वर्ष से अधिक वृद्ध लोगों के लिए मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन को महीने के ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) कर दिया जाएगा
- भारत के हर राशन कार्ड धारक के द्वार पर मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी उच्च प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई के साथ पूरा करने में विफल रहा है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए पश्चिम **बंगाल को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी के ₹8,300 करोड़ रोक दिए**, जिससे सत्तावादी प्रवृत्ति का पता चलता है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एनएसएपी और पीएम मातृ वंदना का बकाया **₹358 करोड़** रोक लिया है, जिससे बंगाल की महिलाएं और बुजुर्ग उनके उचित कल्याण लाभ से वंचित हो गए हैं
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल के मध्याह्न भोजन श्रमिकों की घोर उपेक्षा की है - **3.8 लाख** सहायकों को 6 महीने से अधिक समय से **वेतन का भुगतान नहीं किया गया है**
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए बजट आवंटन 2014-15 में 0.5% से गिरकर 2024-25 में निराशाजनक **0.2%** हो गया है, सीएजी ने भाजपा सरकार द्वारा स्वयं-प्रचार के लिए **एनएसएपी निधि के दुरुपयोग** को उजागर किया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान **111/125 देशों** में है

माँ-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बंगाल के कमजोर लोग सुरक्षित, समर्थित और लचीले बने रहें

- *खाद्य साथी योजना* के तहत, *'दुआरे राशन'* पहल के माध्यम से **9 करोड़ लाभार्थियों** को उनके घर पर खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है
- असंगठित क्षेत्र के **1.5 करोड़** मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिली है. *बीना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना* के तहत लाभ दिया
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 की मासिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे **19 लाख** से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं
- *'मानविक' पेंशन योजना* के तहत, **40%** या उससे अधिक विकलांगता वाले **7 लाख** से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ
- 2011 के बाद से, टीएमसी सरकार ने बंगाल में लगभग **2 करोड़ लोगों** को सफलतापूर्वक **गरीबी से बाहर** निकाला है
- राज्य भर में **हजारों पुरोहितों, इमाम और मुएज़्ज़िन को मासिक वित्तीय** सहायता प्रदान की जाती है

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: यह सुनिश्चित करना कि भारत के गरीबों और कमज़ोर वर्ग लोगों को सम्मान का जीवन सुनिश्चित हो

बंगाल के लिए

- **मिड-डे मील के कुक कम हेल्पर्स का वेतन बढ़ाया जाएगा।** टीएमसी राज्य भर में छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में निस्वार्थ रूप से लगे 2.3 लाख कुक सह सहायकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी।

  हम मिड-डे मील के कुक कम हेल्पर्स का पारिश्रमिक बढ़ाएंगे। ₹1,000 से ₹1,500 अतिरिक्त ₹500 प्रतिमाह के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- **बंगाल में और अधिक माँ कैंटीन स्थापित की जाएंगी।** टीएमसी जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में और अधिक मां कैंटीन स्थापित करना जारी रखेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी भूखा न रहे और सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच की गारंटी हो।

देश के लिए

- **हर राशन कार्ड धारक के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा।** टीएमसी उन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाना जारी रखेगी जो आजीविका के लिए सरकार पर निर्भर हैं।

  हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को उनके दरवाजे पर मासिक 5 किलोग्राम अनाज कोटा प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करके, हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेंगे और इस अभ्यास को सक्षम करने के लिए पूरे देश में आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेंगे।

  बिना डिलीवरी वाहन वाले राशन डीलरों को वाहन खरीदने के लिए ₹1 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चोरी रोकने और डिलीवरी में लीकेज रोकने के लिए मजबूत तंत्र भी विकसित किया जाएगा।

- **60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह किया जाएगा।** टीएमसी वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगी। हम बीपीएल लाभार्थियों को समान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की मौजूदा राशि को संशोधित करेंगे।

  वित्तीय सहायता को पहले के ₹200 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दिया जाएगा। (60-79 वर्ष) और ₹500 प्रति माह (80 वर्ष से ऊपर)।

- **गिग वर्कस के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।** टीएमसी भारत की तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। हम सामाजिक सुरक्षा, ऋण पहुंच प्रदान करने और भारत के गिग कार्यबल में श्रमिकों के अधिकारों का प्रबंधन करने के लिए समर्पित उपाय प्रदान करने के लिए एक नई नीति पेश करेंगे।

  इस नीति के प्रमुख घटक होंगे:

  - श्रमिकों को पंजीकृत करने, लाभ के प्रावधान की सुविधा प्रदान करने और श्रमिकों और प्लेटफार्मों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने के लिए एक गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड
  - स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना कवर सहित एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पैकेज
  - आपात स्थिति के मामले में, या कम/अनियमित काम की अवधि के दौरान गिग श्रमिकों का समर्थन करने के लिए एक फ्लेक्सिबल कोष





संस्कृति का संवर्धन, परंपरा का संरक्षण

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक त्योहारों और गतिविधियों को अधिक मान्यता, नियमित आयोजन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
- एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास परिषद बनाया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र की भाजपा सरकार ने बार-बार बंगाल की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक विरासत को बदनाम किया है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पाठ्यपुस्तकों से उनका नाम हटाकर और विश्व भारती पट्टिका से उनका नाम हटाकर **कई बार कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर का अपमान किया है**
- **पौष मेला,** एक सदी से भी पहले की प्रतिष्ठित शांतिनिकेतन परंपरा, जिसमें सैकड़ों कारीगरों को रोजगार मिलता था, केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा **2019 में अचानक रोक दिया गया**, जिससे इलाके में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 2014 के बाद से गणतंत्र दिवस के लिए **बंगाल की झांकियों को बार-बार अस्वीकार करना** राज्य और उसके सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है
- स्वामी विवेकानन्द को **"अज्ञानी वामपंथी"** बताने से लेकर **विद्यासागर की प्रतिमा** को तोड़ने और **रवीन्द्रनाथ टैगोर के इतिहास** को गलत साबित करने तक, बांग्ला बिरोधी भाजपा ने बार-बार बंगाल की विरासत का अपमान किया है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल, मेघालय और अन्य राज्यों की भाषाई आकांक्षाओं के प्रति उदासीन रही है - मुखर मांगों के बावजूद, **38 भाषाएं** अभी भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार कर रही हैं

माँ-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी बंगाल की समृद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में खड़ी हुई है

- **दुर्गा पूजा** को **'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत'** के रूप में मान्यता दी गई है **यूनेस्को** द्वारा **₹72,000 करोड़** का राजस्व अर्जित करना और **3 लाख लोगों** को रोजगार देना शामिल है
- बिजली बिल में छूट, विज्ञापनों पर कर छूट और फायर ब्रिगेड शुल्क माफ करने जैसे लाभों के साथ-साथ **दुर्गा पूजा क्लबों के लिए ₹70,000 की सहायता,** सांस्कृतिक त्योहारों के उत्सव का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित **शांतिनिकेतन** को **यूनेस्को** द्वारा **'विश्व विरासत स्थल'** के रूप में मान्यता दी गई है
- भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह के पहले संथाली-अंग्रेजी-बंगाली त्रिभाषी शब्दकोश के प्रकाशन के साथ-साथ **संथाली अकादमी** की स्थापना की गई है
- हाल ही में कोलकाता और दीघा में **विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर** स्थापित किए गए हैं, जो व्यवसाय, व्यापार और एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) पर्यटन के लिए जीवंत केंद्र बन गए हैं
- हमारे राज्य की भाषाई विविधता को पहचानते हुए हिंदी, नेपाली, उर्दू, उड़िया, संथाली, राजबंशी आदि को **द्वितीय आधिकारिक भाषा** के रूप में मान्यता दी गई है

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: भारत के विविध समुदायों की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना

बंगाल के लिए

- **बंगाल के सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता की मांग की जाएगी।** हम बिष्णुपुर में मंदिरों, कलिम्पोंग में नेओरा वैली नेशनल पार्क और अन्य स्थलों को राष्ट्रीय सूची में शामिल करने के लिए याचिका दायर करके और प्रासंगिक फाइलिंग की सुविधा के लिए यूनेस्को का अनुसरण करके यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा हासिल करने की दिशा में काम करेंगे।

- **दुर्गा पूजा कार्यक्रमों के लिए क्लबों को वित्तीय सहायता अनुदान जारी रखा जाएगा।** टीएमसी बंगाल के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक त्योहार दुर्गा पूजा को मनाने में क्लबों का समर्थन करेगी।

  हम राज्य भर में दुर्गा पूजा क्लबों को एक व्यापक सहायता पैकेज प्रदान करना जारी रखेंगे, जिसमें ₹70,000 की वित्तीय सहायता, बिजली बिल में छूट, विज्ञापन करों पर छूट और अग्निशमन सेवाओं के शुल्क पर छूट शामिल है।

- **बंगाल के सांस्कृतिक उत्सवों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जायेगा।** टीएमसी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और जश्न मनाना जारी रखेगी।

  हम पौष मेला, बांग्ला संगीत मेला, साहित्य महोत्सव आदि और कई अन्य त्योहारों के वार्षिक आयोजन की सुविधा प्रदान करेंगे।

  इसके अलावा, हम सालाना 'विश्व बांग्ला लोक संस्कृति उत्सव' और 'बांग्लार आदिवासी हस्तशिल्प प्रदर्शनी' का आयोजन करके स्थानीय कारीगरों का समर्थन करना और लोक संस्कृति को संरक्षित करना जारी रखेंगे।

  इसके अतिरिक्त, राजबंशी भाषा अकादमी और मानभूम सांस्कृतिक अकादमी जैसे संगठनों को समुदाय-विशिष्ट कार्यक्रमों की मेजबानी करने का अधिकार दिया जाएगा।

- **गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाएगा।** हम भारत के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थयात्राओं में से एक, गंगा सागर मेले को "राष्ट्रीय मेले" में अपग्रेड करने के लिए याचिका दायर करेंगे, जिससे बेहतर फंडिंग के माध्यम से इस भव्य परंपरा की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

- **एक बांग्ला भाषा अनुसंधान और संवर्धन केंद्र की स्थापना की जाएगी।** टीएमसी बांग्ला भाषा की विरासत का सम्मान, संरक्षण और प्रचार करेगी।

  हम भाषा संरक्षण, बांग्ला के राष्ट्रव्यापी (और वैश्विक) प्रचार को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यात बांग्ला विद्वानों और विशेषज्ञ संकाय के साथ राज्य में एक रवींद्रनाथ टैगोर भाषा अनुसंधान और संवर्धन केंद्र स्थापित करेंगे।

  साहित्य, कविता और कला रूपों में अकादमिक अनुसंधान के माध्यम से सामुदायिक शिक्षा शामिल है ।

देश के लिए

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा।** टीएमसी श्रद्धेय बंगाली और राष्ट्रीय आइकन के लिए प्रशासनिक सम्मान सुनिश्चित करेगी।

  हम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को 23 जनवरी - नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मानित जन्मदिन - को

भारत के आधिकारिक राजपत्र में जोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे।

- **राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास परिषद बनाई जायेगी।**
  स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष परिषद का गठन किया जाएगा, जो सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी।

  परिषद इन व्यवसायों में लगे लोगों के कल्याण को भी प्राथमिकता देगी। बंगाल की तरह ग्रामीण कलाकारों, लोक कलाकारों आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय रंगमंच, संगीत और अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

- **खासी और गारो भाषा को मान्यता।** टीएमसी उत्तर पूर्व में अपने सहयोगी राज्यों की भाषाई जरूरतों का समर्थन करेगी।

  संविधान की 8वीं अनुसूची में उन्हें शामिल करने की मांग करने वाला एक विधेयक पेश करके, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन 2 मेघालयी भाषाओं को विधिवत मान्यता प्राप्त हो, उचित रूप से वित्त पोषित किया जाए और उचित रूप से प्रचारित किया जाए।









संस्कृति परंपरा और पर्यटन, बांग्ला है सबसे उत्तम

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के पर्यटन बुनियादी ढांचे को पुनर्विकासित किया जाएगा जिसमें साझा-उपक्रमों (PPP) के प्रयास शामिल होंगे
- भारत में पर्यटन क्षेत्र की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे

केंद्र सरकार ने क्या किया: केंद्र उस क्षेत्र को प्रभावी ढंग से विकसित करने में विफल रहा है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण क्षमता थी

- **स्वदेश दर्शन योजना एक अप्रभावी दिखावा रही है** - केंद्र विकास के लिए लक्षित 15 सर्किटों में से 14 के लिए विस्तृत योजना बनाने में विफल रहा है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत ₹4,225 करोड़ के कुल व्यय का मात्र 0.7% आवंटित करके **ग्रामीण पर्यटन सर्किट के विकास की उपेक्षा की** है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी सरकार ने अपने पर्यटन उद्योग की क्षमता को लगातार विकसित किया है

- विदेशी पर्यटक यात्राओं के मामले में बंगाल भारत में **तीसरे स्थान पर है और घरेलू पर्यटकों के दौरे के मामले में 8वें स्थान पर है, 20222 तक 8 करोड़ पर्यटक आगंतुक आए**
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुर्शिदाबाद के **किरीटेश्वरी गांव** को 2023 में भारत के **सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार** दिया गया
- बंगाल की होमस्टे पर्यटन नीति होमस्टे मालिकों को ₹1 लाख का प्रोत्साहन देती है, और इससे **2,340 पंजीकृत होमस्टे को लाभ हुआ है,** इस प्रक्रिया में 18,720 नौकरियां पैदा हुई हैं
- **आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया** ताकि क्षेत्र को कर लाभ, कम टैरिफ, सब्सिडी आदि का विस्तार किया जा सके. यह अधिक निवेश आकर्षित करेगा और राज्य में नई नौकरियाँ पैदा करेगा

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: पर्यटन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में बदलना जो हमारे आर्थिक विकास के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

बंगाल के लिए

- **पर्यटन व्यवसायों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बनाया जाएगा।** आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारियों और नोडल एजेंसियों के संचालन को सुव्यवस्थित करके, हम एक डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र स्थापित करेंगे जो सभी आवश्यक परमिटों को 100% ऑनलाइन दाखिल करने और अनुमोदन करने में सक्षम करेगा, जिससे नए व्यवसायों को 21 दिनों के भीतर संचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी।
- **पीपीपी उद्यमों के माध्यम से बंगाल के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा।** टीएमसी होटल, रिसॉर्ट्स, साहसिक गतिविधियों और क्रूज जैसे उच्च-स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देगी।

  पीपीपी दृष्टिकोण के माध्यम से, हम मरीना, जेटी, नौकायन सुविधाओं और तटवर्ती सैरगाहों सहित तटीय पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन को आगे बढ़ाएंगे।

रणनीतिक पीपीपी निवेश के माध्यम से पैरासेलिंग, स्कीइंग आदि जैसे साहसिक खेलों के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा।

राज्य में शुरू किए गए सभी उद्यमों में स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय सर्किट विकसित किये जायेंगे।** टीएमसी जिला-स्तरीय धार्मिक सर्किट स्थापित करके, भक्तों के लाभ के लिए 400 से अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़कर बंगाल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।

  हम इन सर्किटों को आरामदायक तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए सड़कों, आवास और सुविधाओं जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ विकसित करेंगे।

- **बंगाल के आतिथ्य उद्योग के लिए एक आधुनिक गुणवत्ता मान्यता फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा।** पर्यटन को बढ़ाने के लिए, टीएमसी बंगाल में आतिथ्य पेशकश की गुणवत्ता को मजबूत करेगी।

  हम 3 प्रमुख घटकों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर एक गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम तैयार करके बंगाल के पर्यटन उद्योग में आतिथ्य सेवाओं की श्रृंखला में सुधार और मानकीकरण करेंगे:

  - विभिन्न सेवा प्रदाताओं की पहचान और उनके अनुरूप सुधार योजनाओं के लिए एक स्तरीय प्रमाणन प्रणाली (कांस्य, चांदी, सोना, प्लैटिनम स्तर)
  - सेवा प्रदाताओं के लिए उनकी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - स्थापित मानकों के अनुपालन की गारंटी के लिए नियमित ऑडिट की प्रणाली

- **पर्यटक गाइडों को ₹2,500 का मासिक मानदेय दिया जाएगा।** हम राज्य सरकार की पर्यटक गाइड प्रमाणन योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन पूरा करने वाले सभी नए पर्यटक गाइड और अनुभवी पर्यटक गाइड को ₹2,500 का मासिक मानदेय प्रदान करेंगे।

- **राज्य में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे प्रतिष्ठानों को बढ़ावा दिया जाएगा।** टीएमसी पर्यटन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे के विकास की सुविधा प्रदान करेगी।

  हम होमस्टे मालिकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि को कम करने और उनके पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए 'पश्चिम बंगाल होमस्टे पर्यटन नीति 2022' को अपडेट करेंगे।

  हम अधिक होमस्टे मालिकों को ₹1 लाख का प्रोत्साहन देकर, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में होमस्टे की स्थापना को बढ़ावा देंगे. यह पर्यटन स्टार्टअप व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देगा और इन जिलों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगा।

देश के लिए

- **भारत में पर्यटन क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए बड़े प्रयास किये जायेंगे।** टीएमसी विदेशी और घरेलू पर्यटकों की आमद को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ समग्र दृष्टिकोण के साथ भारत के पर्यटन को बढ़ावा देगी।

  हम भारत को दुनिया भर के यात्रियों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल में परिवर्तित करके, उसके आश्चर्यजनक भौगोलिक परिदृश्यों से लेकर उसके विस्मयकारी ऐतिहासिक स्मारकों और जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री तक, हमारे देश की पेशकश

की व्यापकता और गहराई को उजागर करके दुनिया के सर्वोच्च पर्यटन रत्न के रूप में स्थापित करेंगे।

न केवल पेशकशों की एक सम्मोहक श्रृंखला विकसित करने के लिए बल्कि पर्यटन पेशकशों से आर्थिक उत्पादन को अधिकतम करने के लिए भी एक ठोस प्रयास किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था स्वयं आत्मनिर्भर है।

जो उपाय किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पीपीपी में अत्याधुनिक पर्यटन बुनियादी ढांचे, जैसे होटल, रिसॉर्ट, समुद्र तट पर इको-रिट्रीट आदि का विकास
- विभिन्न पर्यटन सर्किट जैसे धार्मिक सर्किट, इको-सर्किट, तटीय सर्किट आदि की स्थापना और संवर्द्धन
- सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए एक समर्पित कोष का निर्माण
- देश भर के गांवों की पहचान करना और उन्हें पर्यटन गांवों के रूप में विकसित करना ताकि आगंतुकों को ग्रामीण जीवन और परंपराओं का एक प्रामाणिक और गहन अनुभव प्रदान किया जा सके और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके
- त्योहारी सीज़न के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को विशेष पर्यटक पैकेज की पेशकश करना ताकि उन्हें भारत के जीवंत सांस्कृतिक समारोहों का पता लगाने के अद्वितीय अवसर प्रदान किए जा सकें
- देश भर में पर्यटन स्थलों पर नाइटलाइफ़ क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ विभिन्न स्वदेशी कला, शिल्प, वस्त्र आदि की विशेषता वाले सांस्कृतिक बाजारों के विकास को बढ़ावा देना




806B
DHR
924
DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY





जैविक विविधता का संरक्षण, लाएगी पर्यावरण मे सन्तुलन

मुख्य लक्ष्य

- बंगाल के वन कवर को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, जिसमें जलमैत्री और आवास संरक्षण पर जोर दिया जाएगा
- भारत की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय विधानों को मजबूत किया जाएगा

केंद्र सरकार ने क्या किया : केंद्र ने बार-बार कॉर्पोरेट हितों की बलिवेदी पर पर्यावरण का बलिदान दिया है

- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल में **चक्रवात राहत के लिए निर्धारित ₹43,508 करोड़ की बड़ी धनराशि को निर्दयतापूर्वक रोक दिया,** जिससे राज्य को उसके उचित बकाये से वंचित कर दिया गया और हमारे लोगों को पूरी तरह से निराशा में छोड़ दिया गया
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केवल 3 वर्षों (2018-2021) में **वन्यजीव पर्यावास निधि में 47% की भारी कटौती की है,** जो अपने स्वयं के बहुप्रचारित वन्यजीव संरक्षण वादों को कमजोर कर रही है
- भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप **30/131 शहर वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी से वंचित हो गए हैं,** जिससे वायु प्रदूषण से निपटने के भारत के प्रयासों को नुकसान हुआ है
- केंद्र सरकार का **नमामि गंगे कार्यक्रम बुरी तरह विफल रहा है** - 71% परीक्षण किए गए स्टेशनों पर प्रदूषण के खतरनाक स्तर का पता चलता रहा है
- **कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत** ने अपर्याप्त आवास तैयारी और खराब प्रबंधन के साथ केंद्र सरकार की वन्यजीव संरक्षण विफलताओं को उजागर कर दिया है
- भाजपा की अपत्यशील लाभ की प्यास ने उत्तरी राज्यों में भूमि का व्यावसायिकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे **जोशीमठ में व्यापक भूस्खलन और बाढ़** का सामना हो रहा है

मां-माटी-मानुष सरकार ने क्या किया: टीएमसी ने स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करते हुए मजबूत पर्यावरणीय प्रबंधन का प्रदर्शन किया है

- वर्ष 2024-25 के लिए पर्यावरण और वन के लिए **₹1,119.6 करोड़** का महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया गया है
- 'बन महोत्सव' और 'सबुजश्री' जैसे कार्यक्रमों ने **90.6 लाख पौधे लगाए हैं और राज्य में 6,618 हेक्टेयर भूमि का वनी करण किया**
- जलदापारा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण प्रयासों के **परिणामस्वरूप राज्य की लुप्तप्राय गैंडों की आबादी में 20% की वृद्धि**
- बंगाल अब सबसे अधिक जैव विविधता विरासत स्थलों (10) के साथ देश में अग्रणी है
- सरकार ने 3 'साल लीफ' विनिर्माण इकाइयां, 5 जैव विविधता पार्क, 4 बटरफ्लाई गार्डन और 4 'अवॉय पुकुर' स्थापित की हैं
- सुंदरवन को जनवरी 2019 में रामसर **कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व** का वेटलैंड घोषित किया गया है

टीएमसी सरकार क्या करने का संकल्प लेती है: वायु और जंगलों की रक्षा करना, स्थिरता बढ़ाना और स्वदेशी समुदायों की रक्षा करना

बंगाल के लिए

- **घाटल मास्टर प्लान को मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारे लोगों को केंद्र की इच्छा पर निर्भर न रखा जाए।

  मास्टर प्लान की बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 19 किमी नदी तट का पुनर्जीवन पहले ही पूरा हो चुका है. हम परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेंगे, भले ही केंद्र अपने वित्तपोषण दायित्वों को पूरा करने में विफल हो।

- **नष्ट हुई आर्द्रभूमियों का धीरे-धीरे पुनर्वास किया जाएगा।** टीएमसी 2032 तक ख़राब हो चुकी आर्द्रभूमियों का पुनर्वास करेगी और इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करेगी। स्वस्थ आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के परिणामस्वरूप राज्य के लिए कार्बन स्टॉक में वृद्धि होगी और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में राज्य की हिस्सेदारी पूरी होगी।

- **समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (सीबीएनआरएम) दृष्टिकोण को बंगाल के पर्यावरण शासन में एकीकृत किया जाएगा।** टीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदायों और/या उनके प्रतिनिधियों को उन परियोजनाओं के लिए परामर्श में अधिक मजबूती से एकीकृत किया जाए जो अपरिवर्तनीय रूप से उनके मौजूदा निवास स्थान या उपभोज्य संसाधनों को प्रभावित करते हैं और उन्हें पारिस्थितिक विविधता की रक्षा, भूमि की रक्षा और वन क्षेत्रों और संसाधनों के प्रशासन के लिए वृद्धिशील अधिकार दिए जाते हैं. पैतृक रीति-रिवाजों को कायम रखेंगे।

- **बंगाल में वन क्षेत्र का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।** टीएमसी राज्य में वन आवरण में वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से, वनीकरण के तहत बंगाल की भूमि का विस्तार (वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र का 19%) सुनिश्चित करेगी। नष्ट हुए वनों के पुनर्जीवन और शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में हरित आवरण की वृद्धि के माध्यम से, हम धीरे-धीरे इस अंतर को पाटने के लिए प्रगति करेंगे।

- **सुंदरवन में घटते मैंग्रोव वनों को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा।** टीएमसी सुंदरबन के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल और संरक्षित करेगी।

  हम नष्ट हो चुके क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षों को फिर से लगाने के लिए मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान तेज करेंगे और क्षेत्र में मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में जहां मैंग्रोव पहले से मौजूद नहीं थे, वहां वनीकरण अभियान चलाएंगे।

  हम वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त ख़राब क्षेत्रों की पहचान करने, नए लगाए गए मैंग्रोव के विकास और जीवित रहने की दर की निगरानी करने के लिए आधुनिक तकनीक को तैनात करेंगे, और आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि चल रहे निगरानी डेटा के जवाब में अनुकूली प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया जा सके।

- **उत्तर बंगाल की विभिन्न नदियों के बनफियों को कटाव से बचाने के लिए उपाय लागू किये जायेंगे।** टीएमसी का लक्ष्य मालदा में गंगा सहित उत्तर बंगाल की नदियों को कटाव से बचाने और समुदायों को बाढ़ से बचाने के लिए रणनीतियों को लागू करना है।

  हम एक व्यापक योजना विकसित करेंगे और नदी के किनारों को स्थिर करने और कटाव को कम करने के लिए विलो और गहरी जड़ें वाली वनस्पति लगाने जैसे कटाव नियंत्रण उपाय करेंगे।

देश के लिए

- **वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर दोबारा विचार किया जाएगा।** टीएमसी भारतीय वन अधिनियम (1927) के अनुसार 'वन' के रूप में दर्ज भूमि की पवित्रता को संरक्षित करेगी।

  हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वन भूमि का गैर-जिम्मेदाराना हस्तांतरण न हो, जैसे गैर-वन उपयोग, सड़क के किनारे सुविधाओं का निर्माण, सफारी और पर्यावरण-पर्यटन गतिविधियाँ।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा।** वायु प्रदूषण के लगातार हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए टीएमसी बेहतर रणनीति लागू करेगी।

  हम अधिक सटीक और व्यापक डेटा प्राप्त करने, उद्योगों और बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों की समीक्षा और अद्ध्यन करने और परिवहन, उद्योग, कृषि (स्टबल बर्निंग) के लिए आधुनिक क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों को विकसित करने के लिए देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या और कवरेज बढ़ाएंगे), और वायु प्रदूषण के सबसे प्रमुख औद्योगिक स्रोतों से निपटने के लिए निर्माण करेंगे।

- **खनन से संबंधित कानून की व्यापक समीक्षा की जाएगी।** पर्यावरण सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और श्रम सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की दृष्टि से, हम खनन पर भारत के पुराने कानून की गहन जांच करेंगे।

  खनिजों के सतत उपयोग, पारिस्थितिक क्षति के लिए अत्याधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए खान अधिनियम (1952), खान और खनिज अधिनियम (1957), और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के प्रावधानों की फिर से जांच और आधुनिकीकरण किया जाएगा. शमन रणनीतियाँ, और खनन श्रमिकों की सुरक्षा।





धन्यवाद ज्ञापन

अपने वादों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई है, और पिछला दशक बंगाल के सभी क्षेत्रों में हुए समग्र विकास का प्रमाण है। अथक प्रयासों के माध्यम से, हमने एक समृद्ध और समावेशी बंगाल का निर्माण किया है, जहां सभी समुदाय सद्भाव से रहते हैं, जहां आपके बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच है, जहां आपके अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कल्याण सभी तक पहुंचता है।

वह यात्रा जिसकी नींव रखते हुए हमने 13 साल पहले एक साथ शुरुआत की थी वह स्वनिर्भर बांग्ला कायम रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, हम आपका अटूट समर्थन चाहते हैं।

बंगाल की समृद्ध विरासत, संघर्ष का इतिहास और गौरवशाली उपलब्धियाँ हमारा सामूहिक गर्व हैं और इन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में, बाहर की दमनकारी ताकतों ने, हमारी संस्कृति और इतिहास का तिरस्कार करते हुए, हमारे राज्य को लगातार धोखा देने, विभाजित करने और वंचित करने की कोशिश की है, जिससे हर चरण में उनकी बंगाल विरोधी साख स्पष्ट हो गई है।

बंगाल के लोग हमेशा परिवर्तन और प्रतिरोध में सबसे आगे रहे हैं, सभी प्रकार के विभाजन, प्रचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी इन बांग्ला विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर देश के बाकी हिस्सों के लिए मार्ग प्रशस्त करें।

आपका विश्वास, समर्थन और प्रचंड गर्जना इन जोमिदारों को समाप्त करने, उन्हें बंगाल और भारत से हमेशा के लिए बाहर निकालने की तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उद्देश्य से, हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट जोड़ा फूल चुनाव चिह्न पर दें और 18वीं लोकसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करें।

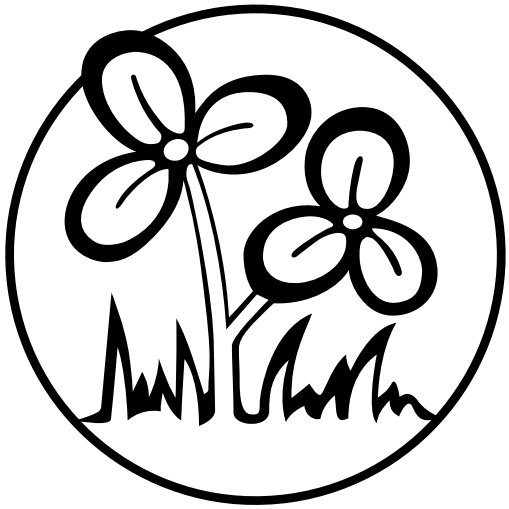
आइए, मिलकर प्रगति और समृद्धि के युग की शुरुआत करते हुए अपनी माँ, माटी, मानुष के अधिकारों को सुरक्षित करें!

जय हिंद! जय बांग्ला!

प्रस्तुति

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस





अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

बंगाल की विरासत और गर्व की रक्षा करें
इस चुनाव चिह्न पर अपना वोट दें



अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिषेक बनर्जी
और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष, सुब्रत बक्षी द्वारा प्रकाशित
मुद्रण: एडीओ प्रिंट, कोलकाता - 700135

AITCofficial | aitcofficial | AITCofficial